

**परियोजना: औपनिवेशिक अभिलेखीय नीति 1858-1947, और
भारत में प्रारंभिक आधुनिक इतिहास लेखन
सबासाची भट्टाचार्य, टैगोर नेशनल फेलो, राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा।**

परियोजना कार्य के पहले चरण, जून 2012 - नवंबर 2012 पर रिपोर्ट।

समीक्षाधीन अवधि (जून 2012 से नवंबर 2012) में 1858 से 1872 तक की अवधि के दस्तावेजों की जांच की गई है। शुरुआती निष्कर्ष इस प्रकार हैं: इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग की रिकॉर्ड श्रृंखला राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध है, और हालांकि वे विभागीय रिकॉर्ड सभी शोधकर्ताओं के लिए खुले नहीं हैं, इसके लिए डीआईजी, एनएआई की अनुमति, की आवश्यकता है। यह अनुमति मुझे महानिदेशक द्वारा आसानी से दी गई थी और मैंने उन अभिलेखों की जांच की। इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग की फाइलों में से कोई भी 1890 से पहले की नहीं है। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार (इसके बाद डब्ल्यूबीएसए) में 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड्स रूम की स्थापना से संबंधित कुछ रिकॉर्ड, साथ ही 1861 (पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार सामान्य विभाग, सामान्य शाखा, मई-दिसंबर 1867) में गठित रिकॉर्ड्स समिति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय में बंगाल सरकार के रिकॉर्ड से भारत सरकार के "रिकॉर्ड के पृथक्करण" से संबंधित कुछ रिकॉर्ड रखे हैं। इसके अलावा, डब्ल्यूबीएसए में 1830 में जनरल रिकॉर्ड्स ऑफिस की स्थापना से संबंधित कुछ 1860-से पूर्व के रिकॉर्ड शामिल हैं, जो बंगाल और भारत सरकार के रिकॉर्ड दोनों का संग्रहस्थान था। राष्ट्रीय अभिलेखागार के संबंध में, सबसे अच्छा स्रोत सार्वजनिक विभाग, सार्वजनिक शाखा, के फाइलों की श्रृंखला है; विशेष रूप से गृह (सार्वजनिक) दिसंबर 1872, सं. 647 और इसी अनुक्रम में रिकॉर्ड समिति के संबंध में भारत सरकार की कार्यवाही का एक अच्छा सारांश है, जिसकी मैंने डिजिटल प्रतियां खरीदी हैं (संयोग से डिजिटल प्रतिलिपि एनएआई में महंगी है)। उपर्युक्त दस्तावेजों में जो विकास हो सकता है, उस विकास की एक रूपरेखा निम्नानुसार है:

ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन की समाप्ति के बाद भारत सरकार के अभिलेखों को क्रम में रखने का प्रयास किया गया था। पुराने रिकॉर्ड को नष्ट करने के पिछे मूल प्रेरणा कलकत्ता में भारत सरकार के कार्यालयों में रिकॉर्ड संरक्षण पर जगह और व्यय को बचाने की है। वित्त आयोग और सिविल लेखा परीक्षक ने (वह बाद के दिनों में कैंग की तरह थे, सिवाय इसके कि सैन्य लेखा परीक्षा एक अलग लेखा परीक्षक द्वारा की गई थी) सिफारिश की है कि उन फाइलों को जो उपयोगी होने की संभावना नहीं है तथा उन पुराने दस्तावेजों को "अपशिष्ट कागज" के रूप में बेचने हेतु उनकी पहचान करने के लिए फाइलों का निपटान किया जा सकता है। इस प्रकार, जिज्ञासापूर्वक, अभिलेखों को नष्ट करने के प्रस्ताव हेतु 1858 के बाद दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए संगठित प्रणाली की शुरुआत की थी। प्रारंभ में वित्त आयोग को रिकॉर्ड संग्रह छाटने का कार्य सौंपा गया था, और शायद कार्य की मात्रा और जटिलता के कारण, आयोग ने उनकी अक्षमता स्वीकार की। इसके बाद, अप्रैल 1861 में भारत सरकार ने ध्यान से चयन करने के

बाद, जो कुछ संरक्षण के लिए सांख्यिकीय या ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, सार्वजनिक कार्यालयों में सभी बेकार रिकॉर्डों को नष्ट करने के लिए इस योजना का संचालन करने के उद्देश्य से "एक रिकॉर्ड कमेटी नियुक्त की थी। (गृह विभाग, सार्वजनिक शाखा, दिसंबर 1872, संख्या 647, रिकॉर्ड समिति, पैरा 3 एनएआई)। यह रिकॉर्ड कमेटी वह संस्था बन गई जिसने अभिलेखीय नीति तैयार की और उस संबंध में सरकार को सिफारिशें की।

रिकॉर्ड समिति के तीन चरण

व्यापक रूप से समिति की गतिविधियां तीन चरणों में घटित होती हैं: (1) 1861 से 1865 तक रिकॉर्ड समिति ने दो विकल्प बनाने के लिए अभिलेखीय नीति पर विचार-विमर्श किया, या तो सरकार को एक केंद्रीय 'म्यूनिमेंट रूम' यानी रिकॉर्ड रूम स्थापित करना चाहिए, या विभिन्न विभागों में अपने स्वयं के रिकॉर्ड रूम होने चाहिए और संरक्षण के लिए दस्तावेज चयन उनसे संबंधित विषय थे। पहला विकल्प पहली बार जून 1861 में समिति की रिपोर्ट में अनुशंसित किया गया था। दूसरा विकल्प अगस्त 1863 में समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुशंसित किया गया था। कुछ दिक्कतों के बाद, 1865 में बाद के विकल्प को भारत सरकार द्वारा चुना गया था। रिकॉर्ड कमेटी द्वारा अनुमानित अभिलेखन का काम बहुत अधिक था, जो कि उनके अनुमान से केवल मौजूदा फाइलों के 16,255 से अधिक वॉल्यूम और 16,300 बंडल थे। रिकॉर्ड कमेटी का काम इस तथ्य से बाधित था कि रिकार्ड कीपर और अभिलेखीय कर्मचारियों की नियुक्ति करने की सिफारिशें लगातार भारत सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गईं इस आधार पर कि अतिरिक्त व्यय से बचा जाना चाहिए। सरकार द्वारा स्वीकृत एकमात्र पद जे. टी. व्हीलर समिति के सचिव के रूप में, अंशकालिक के रूप से 500 रुपये प्रति माह के वेतन के साथ कार्यरत था। भारत सरकार 1857 के विद्रोह के दौरान सैन्य व्यय में भारी वृद्धि के कारण वित्तीय संकट और ऋण बोझ से धीरे-धीरे उभर रही थी। इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड कमेटी को वित्तीय सहायता से इंकार कर दिया। रिकॉर्ड कमेटी को वास्तव में उस जिम्मेदारी के निर्वहन के साधनों के बिना ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। (2) 1865 से 1869 तक केंद्रीय रिकॉर्ड रूम की कोई और चर्चा नहीं है। रिकॉर्ड कमेटी के सचिव, जे. टी. व्हीलर, कुछ राज्य दस्तावेज के प्रकाशन की तैयारी में लगे थे लेकिन 1869 तक वे कार्य पूरा करने में असमर्थ थे तब उन्होंने ब्रिटिश बर्मा आयोग में उच्च पद में शामिल होने के लिए समिति छोड़ दी थी। रिकॉर्ड कमेटी के वेतनभोगी सचिव का पद इस प्रकार खाली हो गया और फिर कभी भरा नहीं गया। रिकॉर्ड कमेटी के सदस्यों ने विभागीय रिकॉर्ड रूम स्थापित करने और पुरानी कागजात को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ विभागों का दौरा किया। चूंकि नियमित अभिलेखीय कर्मचारियों पर व्यय अधिक खर्चीला होने का अनुमान लगाया गया था, भारत में उच्च अधिकारियों और 'गृह अधिकारियों' ने चुनिंदा दस्तावेजों को प्रकाशित करने का सस्ता विकल्प पसंद किया। (3) 1869 से 1872 तक एक चरण था जब सरकार चुनिंदा रिकॉर्ड और कैलेंडर प्रकाशित करने की योजना पर कार्य करने की स्थिति में लौट आई और निर्णायक रूप से केंद्रीय रिकॉर्ड रूम के विचार को त्याग दिया। इस मामले में सर विलियम हंटर की सलाह निर्णायक थी:

सार्वजनिक रिकॉर्ड ऑफिस की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे इंग्लैंड और यूरोप में कहीं और मौजूद थे। वाइसराय नॉर्थब्रुक का मानना था कि यह कुछ दस्तावेजों को चुनिंदा रूप से प्रकाशित करने के राजनीतिक उद्देश्य से कार्य करेगा। इस प्रकार एक अभिलेखीय नीति पर विचार-विमर्श इस चरण में केंद्रीय रिकॉर्ड रूम के लिए योजना को अस्वीकार करने और इंपीरियल पास्ट के चुनिंदा दस्तावेजों के प्रकाशन की प्राथमिकता के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद मैं उपर्युक्त रिपोर्ट के अधिक महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान केंद्रित करूंगा।

अभिलेखीय नीति बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व

क्राउन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत सरकार का अधिभार ग्रहण करने के बाद पहले दशक में रिकॉर्ड के संगठन और संरक्षण के लिए इसमें रुचि रखने वाले और इसकी जिम्मेदारी लेने वाले लोग कौन थे? क्या वे वह व्यक्ति थे जो ऐतिहासिक हित में रिकॉर्ड्स कमेटी 1861- 1872 के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गये थे? एनएआई रिकॉर्ड में फाइलों के नामों को छोड़कर कोई सुराग नहीं है, लेकिन 19वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास से जो परिचित थे वे ऐतिहासिक अनुसंधान में ऐतिहासिक हित और उपलब्धियों से संबंधित कई सदस्यों की पहचान कर सकते हैं। समिति के पहले सचिव रेव. जे. लांग (1814-1887) थे, जो कलकत्ता इन ओल्डन टाइम्स (1852) में अपने पुराने रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिए और भारतीय भाषाओं के उनके ज्ञान के लिए जाने जाते थे। (उन्होंने अंग्रेजी इंडिगो प्लांटर्स द्वारा मूल निवासी के शोषण पर प्रकाश डालने वाले एक बंगाली नाटक नील दर्पण से अनुवाद किया)। समिति के पहले अध्यक्ष आईसीएस के जेम्स सी. एरस्किन (1821 - 1893) थे। जिन्होंने अपने पिता विलियम एरस्किन (1773- 1852) के कार्य, बाबर और हुमायूं (1852) के अधीन भारत का इतिहास संपादित और प्रकाशित किया; वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु और बॉम्बे प्रेसीडेंसी में निदेशक, सार्वजनिक निर्देश भी थे। तीसरे सदस्य रिचर्ड टेम्पल (1826- 1902) थे जिन्होंने बाद में जेम्स थॉमसन (भारत के शासक श्रृंखला, ऑक्सफोर्ड, 1893) का जीवन चित्रण किया था और 1880 (लंदन, 1881) में भारत के उनके प्रसिद्ध कार्य में कुछ ऐतिहासिक रुचि दिखाई थी। अगले 10 वर्षों में समिति में शामिल होने वालों में से, कुछ ऐसे थे जिनके पास उनके नाम पर ऐतिहासिक कार्य थे। जेम्स टैलबॉय व्हीलर (1824- 1897) इंग्लैंड में एक पुस्तक विक्रेता के रूप में एक साधारण पृष्ठभूमि से आए, जिन्होंने मद्रास स्पेक्ट्रेटर के संपादक के रूप में काम किया, और मद्रास इन ओल्डन टाइम्स, 1639- 1748 (मद्रास, 1882) के शीर्षक के तहत पुराने मद्रास रिकॉर्ड संपादित किए। 1862 से 1870 तक विदेश विभाग में भारत सरकार के सहायक सचिव के रूप में कार्य करते हुए, उन्हें रिकॉर्ड कमेटी में लाया गया था। वे 1863 से 1869 तक समिति के एकमात्र वेतनभोगी सचिव थे। उनके ऐतिहासिक कार्यों में, ब्रिटिश शासन (1886) के तहत भारत को पाठ्य पुस्तक के रूप में जाना जाता था। वे अर्ली ट्रैवेलर्स इन इंडिया (1864 में प्रकाशित एस. पुरचास और जे.एच.वन लिन्सचोटेन पर चित्रण), और अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया (लंदन, 1878) के लेखक भी थे।

जबकि आईसीएस के बाहर से व्हीलर या रेव लांग, रिकॉर्ड कमेटी के सचिवों के रूप में कार्यरत थे, अध्यक्ष हमेशा ही एक विशिष्ट सिविल सर्वन्ट थे। उनमें से आखिरी एक डब्ल्यू.एस. सेटन-कर्क थे, आईसीएस जिन्होंने सिलेक्शन्स फ्रॉम कलकत्ता गैजेट, 1784- 1823 (छः खंड, 1864- 69) और मार्क्विस ऑफ कॉर्नवालिस (भारत के शासक श्रृंखला, ऑक्सफोर्ड, 1893) से संकलन संपादित किए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एनएआई की फाइलों में रिकॉर्ड्स कमेटी के व्यक्तियों के अध्ययनशील रुचि के संबंध में कोई सुराग नहीं है। हालांकि, रिकॉर्ड्स समिति ने सम्भवतः इस तरह की रुचि के साथ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया हो। 1860 के उत्तरार्ध में शामिल सदस्यों में "ए कोल्विन " शामिल थे। शायद ऑकलैंड कोल्विन जिन्होंने उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (बाद में 1887- 1892 में एनडब्ल्यूपी और औध के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के लिए) में आईसीएस में कार्य किया था और सर विलियम हंटर द्वारा संपादित इतिहास पुस्तक श्रृंखला में भारत के शासक पर एक जीवनी वृत्तांत लिखा। "डॉ मौउत "जाहिर है डॉ. फ्रांसिस जे. मौउत (1816- 1897) जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में शिक्षक थे। कुछ समय के लिए जेम्स केव-ब्राउन ने रिकॉर्ड कमेटी पर कार्य किया; वह इंडियन इन्फैंटैटिसाइड, इट्स ओरिजन, प्रोग्रेस, एंड सप्रेषन (लंदन, 1857) पर एक ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक थे।

भारत के उच्च अधिकारियों में से, ए. ओ. ह्यूम, आईसीएस ने रिकॉर्ड कमेटी के बाहर रहकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें मुख्य रूप से उन अंग्रेजों में से एक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रयोजनों के लिए अभिलेखन के कार्य के एक महत्वपूर्ण समर्थक के रूप में भी याद किया जाना चाहिए: यह उनका ही योगदान था कि, भारत सरकार में गृह विभाग के सचिव के रूप में और बाद में राजस्व और कृषि विभाग में, जब रिकॉर्ड कमेटी प्रशासनिक समर्थन को प्राप्त करने के लिए छटपटा रही थी। रिकॉर्ड कमेटी का एक अन्य मित्र वाइसरॉय काउंसिल के वित्त सदस्य सर चार्ल्स ट्रेवेलियन थे; उन्होंने रिकॉर्डर समिति को वेतनभोगी सचिव के पद में व्हीलर को नियुक्त करने में मदद की। रिकॉर्ड कमेटी के बाहर के लोगों में से, सर विलियम हंटर अभिलेखीय नीति निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। वह 1862 में बंगाल प्रेसिडेंसी में आईसीएस में शामिल हो गए और जल्द ही उन्होंने ग्रामीण बंगाल (1868) के वार्षिकवृत्तांत का निर्माण किया, जो एक ऐतिहासिक वृत्तांत है जिसका अभी भी उल्लेख किया जाता है। यहा बंगाल के सांख्यिकीय विवरण (1875- 77) और इंपीरियल गैज़ेटर (1881) के 20 खंडों का पालन किया गया। वे एक निर्विवाद प्राधिकारी बन गये और गृह सरकार को 1871- 72 में रिकॉर्ड रखने पर उनकी सलाह पर निर्भर होना पड़ा। हंटर एक शानदार लेखक थे जिन्होंने औपनिवेशिक इतिहासलेख से जुड़े दृष्टिकोण का निर्माण किया। पहले उल्लेख किए गए एस्क्रीन, टेम्पल, कोल्विन, इत्यादि सभी द्वारा लिखे गए कई ऐतिहासिक कार्य, हंटर द्वारा संपादित भारत के शासक श्रृंखला का हिस्सा थे। वे अभिलेखों के संग्रह और ब्रिटिश भारत के इतिहास के वर्णन को साम्राज्यवादी मोड़ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके साथ-साथ जब भारतीय मुसलमान (लंदन, 1871), द अर्ल ऑफ मेयो (लंदन, 1876), साथ ही भारतीय

शिक्षा आयोग (कलकत्ता, 1883) की रिपोर्ट के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान और उनका अंतिम प्रमुख कार्य मार्क्विस ऑफ़ डलहौसी (भारत के शासक श्रृंखला, ऑक्सफोर्ड, 1895) पर विचार करते हैं, तो उनकी अकादमिक स्वीकृति और प्रतिष्ठा निर्विवाद थी।

नीतिगत मुद्दे और विभिन्न दृष्टिकोण

कई नीतिगत मुद्दों पर 1861- 71 में रिकॉर्ड कमेटी के सदस्यों के साथ-साथ भारत सरकार में पदासिन अधिकारियों और उनके बीच मतभेद उभर कर सामने आये। प्रारंभ में रिकॉर्ड कमेटी में सेंट्रल रिकॉर्ड रूम या 'मुनीमेंट रूम' स्थापित करने के पक्ष में एक मजबूत लॉबी थी, क्योंकि इतिहासकार की प्रवृत्ति वाले सदस्यों ने इसे पसंद किया था। इसके अलावा, इंग्लैंड में रिकॉर्ड प्रबंधन का उदाहरण उनके सामने था। अब उसे आम तौर पर भुला दिया जाता है लेकिन यह 19वीं शताब्दी के मध्य भारत के अंग्रेजों के लिए यह एक मॉडल था। उन्होंने 1800 की संसदीय समिति द्वारा निर्धारित पैटर्न को देखा, जिन्होंने राज्य दस्तावेजों के संरक्षण का सवाल उठाया, रिकॉर्ड आयोग जिसने 1800 से 1837 तक इंग्लैंड में कार्य किया था, 1838 में संसद द्वारा अधिनियमित रिकॉर्ड अधिनियम (विक. कैप. 94 के 1 और 2) और मास्टर ऑफ़ रोल्स के निर्देशों के तहत इंग्लैंड में राज्य दस्तावेजों का पुनर्गठन और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से बड़े पैमाने पर अभिलेखीय कर्मचारियों की भर्ती। इसलिए भारत में रिकॉर्ड कमेटी ने शुरू में 1861 में सिफारिश की कि मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज "वर्तमान में, सभी कलकत्ता में बिखरे हुए होने के कारण, एक म्यूनिमेंट रूम में संरक्षित किया जाना चाहिए।" (राज्यपाल से प्रेषण में उद्धृत रिकॉर्ड समिति की सिफारिश-राज्य सचिव के जनरल कौंसिल, इयूक ऑफ़ अरगील, सार्वजनिक सं. 95, 13 दिसंबर 1872, एनएआई)। उस समय रिकॉर्ड कमेटी ने "अंग्रेज राज्य दस्तावेजों से संबंधित मास्टर ऑफ़ रोल्स " का अनुसरण करने वाले सिस्टम की तर्ज पर दस्तावेजों के कैलेंडर्स और कैलेंडर के इंडेक्स की छपाई की भी सिफारिश की। अगर यह सिफारिश लागू की गई थी तो एक केंद्रीय रिकॉर्ड रूम बनाया गया होगा, यानी इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग की तरह एक संग्रह जिसे अंततः 1890 में स्थापित किया गया था, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार का पूर्ववर्ती था।

अंततः विपरीत दृष्टिकोण ही प्रबल रहा, यानी यह विचार कि केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय की जरूरत नहीं थी और न ही खर्चों के मामले में ये किफायती था। अगस्त 1863 में रिकॉर्ड कमेटी के अध्यक्ष ने भारत सरकार को लिखा कि समिति ने अपना मन बदल दिया है; यह उच्च अधिकारियों के विचारों में आयी शिथिलता थी कि व्यय के बारे में मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। नई नीति सिफारिश ने प्रत्येक विभाग के प्रधान कार्यालय को बनाए रखने की अनुमति देने के "स्वामित्व" को रेखांकित किया "समिति द्वारा प्रस्तावित पहले केंद्रीय म्यूनिमेंट रूम के बजाय, थोक में और अपने वर्तमान आकार में रिकॉर्ड शामिल किया हैं।" इस प्रकार एक महंगे केंद्रीय संग्रह का विचार सस्ते विकल्प के पक्ष में छोड़ दिया गया था, संबंधित विभागों की अभिरक्षा में रिकॉर्ड की स्थिति को बनाए रखा गया था। (गृह विभाग, सार्वजनिक शाखा, दिसंबर 1872, सं. 647, पैरा 3-6, एनएआई)।

गृह अधिकारियों ने इस नई योजना को स्वीकार किया लेकिन उन्होंने भविष्य में इतिहासकारों की सेवा के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय की आवश्यकता के बारे में अधिक जागरूकता दिखाई। राज्य सचिव सर चार्ल्स वुड ने केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय के विचार को छोड़ने के लिए भारत सरकार के फैसले के जवाब में लिखा था: "ऐतिहासिक और पुरातन उद्देश्यों के लिए" अभिलेखों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण था। और उन्होंने आगे कहा: "हालांकि, शायद, बाद के उद्देश्यों को केंद्रीय म्यूनिमेंट रूम के गठन द्वारा अत्यधिक बढ़ावा दिया जाएगा, मैं पूरी तरह से, रिकॉर्ड छोड़ने के आपके निर्णय को स्वीकार करता हूं, जिन्हें कई कार्यालयों में संरक्षित किया जाना है, जिनके वे हैं।" (राज्य सचिव, सर चार्ल्स वुड, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, संख्या 19, 12 फरवरी 1866, एनएआई)। स्पष्ट रूप से राज्य सचिव ने रिकॉर्ड के केंद्रीय संग्रहस्थान को प्राथमिकता दी होगी।

ऐसा लगता है कि गवर्नर जनरल काउंसिल के अधिकांश सदस्य अभिलेखागार पर अतिरिक्त व्यय के विरुद्ध थे। उनमें से कुछ, निस्संदेह, अभिलेखागार के मूल विचार के लिए अत्यधिक समर्थन में थे। वर्ष दर वर्ष रिकॉर्ड क्षय हो रहे हैं; और जब तक कुछ उपायों को अपनाया नहीं जाता है, इन उपायों को लागू करने में बहुत लंबा समय लगेगा, यह हो सकता है कि एक निष्क्रिय आयोग की तरह [रिकॉर्ड कमेटी, कभी-कभी इसे आयोग कहा जाता है] उनके जांच के विषयों को उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया है। "(ए.ओ. ह्यूम की दिसंबर 1872, की टिप्पणी गृह (सार्वजनिक) 31 जुलाई, 1871 की फाइल संख्या 647, पेज 10 पर, एनएआई)। इस प्रकार ए.ओ. ह्यूम, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य बने, वाइसराय काउंसिल में अभिलेखागार के समर्थक के रूप में इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, 1865 में केंद्रीय म्यूनिमेंट रूम की योजना को त्यागने के लिए उच्चतम स्तर पर निर्णय दिया गया था, चयनित दस्तावेजों के प्रकाशन को मुद्रित करने का एकमात्र विकल्प खुला था।

यह संभव है कि जनता के लिए खुले केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय के विचार का विरोध आंशिक रूप से राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित था। मुनिमेंट रूम के सवाल पर वाइसराय काउंसिल के 'ई.सी.बी' की फाइलिंग महत्वपूर्ण है। सर एडवर्ड क्लाइव बेली (1821- 1884) के गृह सचिव (1862- 1872) के रूप में उनका एक लंबा कार्यकाल था और उन्होंने विदेशी और राजनीतिक विभाग में भी काम किया था। उन्होंने शब्दों को कम नहीं किया: "आखिरी शताब्दी के रिकॉर्ड भी हैं जो जनता के लिए खुले होने की वजह से असुविधा का कारण बन सकते हैं।" (ईबीड, 'ई.सी.बी.', 19 दिसंबर 1871 की टिप्पणी)। आईसीएस अनुभवी, सर विलियम हंटर के अलावा अन्य किसी पद में राजनीतिक उद्देश्य इतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। वे यह कहकर संतुष्ट थे कि जनता के लिए खुला हुआ एक मुनिमेंट रूम ऐसे मूल निवासियों को लाएगा जिन्होंने प्रेस के लिए काम किया था, अगर किसी भी तरह से मूल निवासी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कोई दिलचस्पी लेते हैं। भारत में, वह 1871 में भारत सरकार से एक प्रश्न के जवाब में लिखते हैं, "ऐसे केंद्रीय कार्यालय [रिकॉर्ड्स का] का उपयोग करने के लिए जिनके पास कार्यक्षमता और समय है ऐसा कोई जनसमुह नहीं है ... जिनमें काफी क्षमता के लेखक पाए जाते हैं ... लेकिन वे एक बहुत छोटा निकाय

बनाते हैं, और उनकी प्रतिभा प्रेस या वर्तमान साहित्य के अन्य रूपों को समर्पित हैं, उन बड़े अनुसंधान की बजाय जो एक यूरोपीय कैपिटल सब्सर्व में एक राज्य दस्तावेज कार्यालय में है। ' (ईबीड, डब्लू. डब्ल्यू. हंटर से ए.पी. हॉवेल, भारत सरकार, 17 नवंबर 1871, संख्या 649, एनएआई)। यह यूरोपीय टाईप के केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय के भारत में खुलने के खिलाफ हंटर के तर्क का एक हिस्सा था; दूसरा हिस्सा यह था कि भारतीय सरकार को यूरोपीय पैटर्न के केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जिस पर प्रति वर्ष तीस हजार पाउंड स्टर्लिंग खर्च होगा। हंटर की राय निर्णायक थी क्योंकि एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी और उनकी राय यह थी कि शोधकर्ताओं के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड ऑफिस की आवश्यकता के लिए भारत देश अभी बहुत पिछड़ा था, और न ही भारत इसके खर्च का वहन कर सकता था।

संभावित निष्कर्ष: अभिलेखीय नीति के वैकल्पिक मॉडल

यहां सर्वेक्षण की गई अवधि में अभिलेखीय नीति के संबंध में विकास और विचार-विमर्श से क्या संभावित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? शायद 1872 तक की कहानी को निम्नानुसार समझाया जा सकता है: भारत में ब्रिटिश एक अभिलेखीय नीति विकसित कर रहे थे जो नीतिगत स्तर की सोच में अंतर्निहित कुछ ध्रुवीय विरोधियों के बीच आ गया थी। व्यक्तिगत नीति निर्माता इन अलग-अलग स्थितियों को भी अपना रहे थे। नीतिगत स्तर की सोच में अंतर्निहित वैकल्पिक मॉडल के बीच ध्रुवीयताएं निम्नानुसार थीं: (1) सबसे पहले, 1860 के दशक में दो विपरीत मॉडल थे - एक विकेंद्रीकृत विभागीय आधार पर अभिलेखीय संगठन का, जो कि केंद्रीकृत रिकॉर्ड ऑफिस या "मुनीमेंट रूम" की अवधारणा के विपरीत था। (2) दूसरा, भारत में ब्रिटिश शासन के दस्तावेज बनाने के कार्य के बारे में दो अलग-अलग विचार थे: एक विचार स्थायी रूप से सुलभ अभिलेखीय में दस्तावेजों को इकट्ठा करना और संरक्षित करना और कैलेंडर करना था, दूसरा उपलब्ध दस्तावेजों से संकलन प्रकाशित करना था और इस दृष्टिकोण में भावी शोध के लिए अभिलेखीय संग्रह बनाने के कार्य को कम प्राथमिकता दी गई थी। (3) एक और मुद्दा था: नौकरशाही विशेषाधिकार (यानी सिविल सेवा में अंग्रेज) के आधार पर अधिकृत दस्तावेजों तक पहुंच सीमित करने की नीति, और ऐतिहासिक शोधकर्ताओं सहित इच्छुक लोगों तक पहुंच की इजाजत देने के विरोध के बीच चुनाव करना था। (4) परस्पर विरोधी नीति धारणाओं का चौथा क्षेत्र ज्ञानमीमांसीय स्तर पर किया गया था: अभिलेखागार का उद्देश्य ऐतिहासिक ज्ञान का अधिग्रहण, संरक्षण और प्रसार करने का है, या यह उद्देश्य कुछ ज्यादा ही सीमित है, जैसे प्रशासन के साधन के रूप में दस्तावेज का उपयोग करना? निहितार्थ से इस मुद्दे पर सवाल ज्ञान और शक्ति के बीच का संबंध था।

इन व्यक्तित्वों की प्रवृत्ति जिसे एरिक स्टोक्स ने "कठोर-उग्र साम्राज्यवादी" कहा है, निम्नलिखित का चयन करने की थी (क) केंद्रीय अभिलेखागार के बिना विभागीय विकेंद्रीकरण (ख) चुनिंदा प्रकाशन के लिए और भावी पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करने का सार्वभौमिक एजेंडा नहीं है (ग)

नौकरशाही के बाहर के शोधकर्ताओं सहित, जनसामान्य को अभिलेखागार की पहुंच से बाहर रखना है (घ) और समग्र नीति के लिए जो औपनिवेशिक शासन के लिए मुख्य रूप से एक उपकरण के रूप में संग्रहित करना है। हालांकि, जैसा कि हमने पहले देखा है, हमने जिस शुरुआती चरण में अध्ययन किया है, उसमें विपरीत दृष्टिकोण को पूरी तरह से अभिलेखीय नीति के विचार-विमर्श में प्रस्तुत नहीं किया गया था। 1890 के बाद के चरणों में इन नीति विकल्पों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था और नीति बनाने की बोलीभाषा अधिक स्पष्ट हो गई क्योंकि औपनिवेशिक सरकार का अभिलेखागार नीति के बारे में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ है। इस रिपोर्ट के अगली किस्त में उन मुद्दों को अधिक स्पष्ट करने की आशा करते हैं।

सबासाची भट्टाचार्य

**संस्कृति अनुसंधान के लिए टैगोर राष्ट्रीय फेलोशिप
(छह मासिक रिपोर्ट के लिए टेम्पलेट)**

1. संस्थान : राष्ट्रीय अभिलेखागार
2. टैगोर राष्ट्रीय फेलो का नाम : सबासाची भट्टाचार्य
3. फेलोशिप कार्यकाल : 4 जून 2012 से 3 जून 2014 तक
4. अवधि के लिए रिपोर्ट : दिसंबर 2012 से जून 2013
5. छह-मासिक रिपोर्ट : संख्या II
6. परियोजना शीर्षक : औपनिवेशिक अभिलेखागार नीति, 1858- 1947,
और भारत में प्रारंभिक आधुनिक इतिहास लेखन
7. अवधि के दौरान किए गए अनुसंधान
कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी : संलग्न टिप्पणी / रिपोर्ट के माध्यम से।
8. कार्यप्रणाली : इस रिपोर्ट के अनुलग्नक -II के माध्यम से
9. कोई नहीं, क्योंकि प्रकाशन केवल वर्तमान शोध के बाद के चरण में व्यवहार्य होगा।
10. उपर्युक्त के रूप में; फेलोशिप नियमों में निर्धारित सार्वजनिक व्याख्यान का पाठ तैयार है और मैंने
पूर्व डीजी, एनएआई प्रोफेसर एम. हसन को लिखा था की जब भी मुझे बुलाया जाएगा व्याख्यान देने
के लिए मैंने मेरी तैयारी दर्शायी है।
11. क्षेत्र के कार्य पर टिप्पणी : ऊपर मद 8 देखें।
12. परियोजना की मुख्य विशेषताएं / प्रगति : संपूर्ण रूप से कालक्रम के अनुसार,
आधी शताब्दी 1872- 1911 की अवधि कवर की है
और ब्रिटिश शासन के अंतिम 35 वर्षों का पता
लगाना बाकी है
13. कठिनाइयां, यदि कोई हो : एनएआई में कार्य परिस्थितियां अति उत्कृष्ट हैं।

14. अन्य अकादमिक कार्य

: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 1920-1947 की अवधि में मेरी पांडुलिपि पुस्तक को प्रकाशन के लिए स्वीकार कर लिया है। मैंने 16 मार्च 2013 को सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल, कलकत्ता में वार्षिक व्याख्यान दिया है। आईसीएचआर के रूप में कार्यालय के विघटन के बाद मेरा उनके जर्नल इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू को संपादित करना जारी है।

फेलो/स्कॉलर का हस्ताक्षर और तिथि:

संस्थान के प्रमुख की टिप्पणियां:

हस्ताक्षर और तारीख:

परियोजना: औपनिवेशिक अभिलेखीय नीति, 1858-1947, और

भारत में प्रारंभिक आधुनिक इतिहास लेखन

सबासाची भट्टाचार्य, टैगोर नेशनल फेलो, राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा

परियोजना कार्य, दिसंबर 2012 से जून 2013 की दूसरी रिपोर्ट

समीक्षाधीन अवधि (दिसंबर 2012 से जून 2013) में परियोजना के कार्य पर यह रिपोर्ट निम्नलिखित भागों में शामिल है: शुरुआत में एक कार्यकारी सारांश के बाद अकादमिक भाग आता है जो डीजी, एनएआई को 12 दिसंबर, 2012 को प्रस्तुत पहली रिपोर्ट के पैटर्न का पालन करता है।

कार्यकारी सारांश:

1858 से 1872 के लिए एकत्र की गई पहले के रिपोर्ट डेटा में प्रारंभिक विश्लेषण के साथ कवर किया गया था। (तैयार संदर्भ के लिए पहली रिपोर्ट संलग्न है, अनुलग्नक संख्या 1) वर्तमान रिपोर्ट में वर्ष 1872 से 1911 तक की अवधि शामिल हैं। यहाँ यही कहना है कि पूरी तरह से कालक्रम के अनुसार, परियोजना में अध्ययन के तहत अवधि के पहले 50 वर्षों के लिए डेटा संग्रह पूरा हो चुका है, और अगले एक साल में 35 साल कवर किया जाना बाकी है। इसके अलावा, दिल्ली में एनएआई में उपलब्ध आंकड़ों के अलावा, कलकत्ता में अभिलेखागार के आंकड़ों की खोज की गई है; उत्तरार्द्ध इस रिपोर्ट में कार्यप्रणाली पर संलग्न टिप्पणी में बताए गए कारणों के लिए कलकत्ता से नई दिल्ली तक राजधानी के स्थानांतरण से पहले की अवधि प्रासंगिक है (अनुलग्नक II), जून 2013 में एक वर्ष के पूरा होने पर मैंने डीजी, एनएआई, डॉ हसन को एनएआई में सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए मेरी तैयारी का संकेत देते हुए लिखा है; व्याख्यान का पाठ तैयार है और एनएआई किसी भी उचित समय पर व्याख्यान देने के लिए मुझे बुला सकता है। इस रिपोर्ट का अकादमिक हिस्सा निम्नलिखित बिंदुओं को संबोधित करता है। इस परियोजना की पहली रिपोर्ट ने पहले चरण, वर्ष 1858- 1872 का अध्ययन किया और वर्तमान रिपोर्ट में दो बाद के चरणों, वर्ष 1872 - 1891 और वर्ष 1891 - 1911 का अध्ययन किया गया है। वर्ष 1872 के चरण में शाही रिकॉर्ड्स विभाग के गठन के लिए, 1891 - आज के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पूर्ववर्ती- ध्यान में रखने के लिए मुख्य बिंदु है (क) 1872 में रिकॉर्ड कमिटी को समाप्त करने के बाद अभिलेखीय नीति बनाने में अनिश्चितता (ख) 1889-91 में इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग शुरू करने का निर्णय, (ग) ब्रिटिश भारतीय सरकार के उद्देश्य अभिलेखागार के गठन की ओर अग्रसर हुए। अगले चरण में, 1891 से 1911 में कलकत्ता से नई दिल्ली तक राजधानी के स्थानांतरण के लिए, नीतिगत रुझान हैं: (क) स्थायी रूप से नियोजित अधिकारी को रिकॉर्ड के प्रभारी के रूप में रखने के लिए, अंततः रिकॉर्ड्स कीपर के रूप में नामित किए गए; (ख) नए गठित रिकॉर्ड विभाग के लिए एक अभिलेखागार कार्यक्रम का गठन (ग) अभिलेखागार के अंग्रेजी मॉडल का प्रभाव, (घ) मूल भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और जनता को आम तौर पर सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने में अस्वीकार करने की नीति।

चरण II : 1872- 1891

1872 और 1891 के बीच के वर्षों में इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफिस के इतिहास के दूसरे चरण का गठन हुआ। वर्ष 1891 को इस चरण का अंत माना जा सकता था, जब अभिलेखागार के विकास के लिए एक निर्णायक मोड़ दिया गया था- इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के पहले प्रमुख की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1872- 1891 में मुख्य नीतिगत रुझान निम्नानुसार थे:

नीति बनाने में अनिश्चितता की अवधि;

(1) 1870 के दशक और 1880 के दशक में भारत सरकार ने अपनी अभिलेखीय नीति के बारे में अनिश्चितता की इस अवधि के दौरान निराश किया। उस अनिश्चितता का मुख्य कारण 1891 तक केंद्रीकृत रिकॉर्ड विभाग या 'मुनीमेंट रूम' शुरू करने के संबंध में निर्णय लेने में विफलता थी। इसका विकल्प विभिन्न विभाग जैसे विदेशी विभाग, सैन्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, वित्त और वाणिज्य विभाग इत्यादि में रिकॉर्ड रखने के विकेंद्रीकृत प्रणाली को बनाए रखना था, साथ ही समय-समय पर नियोजित शिक्षा सेवा या शौकिया ब्रिटिश इतिहासकारों से भर्ती किए गए संपादकों की सहायता से रिकॉर्ड से संकलनों को प्रकाशित करने की नीति थी। इसके बाद की योजना का एकमात्र परिणाम जे. टैलबॉय व्हीलर द्वारा अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया (लंदन, 1878) शीर्षक के तहत दस्तावेजों के संकलन का प्रकाशन था जिसे मद्रास प्रेसीडेंसी की शैक्षणिक सेवा से प्रतिनियुक्ति आधार पर कलकत्ता लाया गया था। व्हीलर का मानना था कि प्रशासनिक अभिलेखों के विस्तीर्णता में ऐतिहासिक हित नहीं था और इसलिए, उन कुछ रिकॉर्डों में से संकलन का प्रकाशन सार्थक नहीं था; उसे सरकार द्वारा रिकॉर्ड के आगे के प्रकाशन को रोक दिया गया। वह विचार राज्य सचिव की पूर्व सलाह के साथ-साथ 1872 में वाइसरॉय नॉर्थब्रुक के अधीन भारत सरकार के निर्णय के खिलाफ था। (भारत सरकार के राज्य सचिव से प्रेषण, संख्या 95, 13 दिसंबर, 1872)। प्रकाशन पर लगाई गयी रोक 1887 में राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस के ध्यान में आई और उन्होंने रिकॉर्ड के प्रकाशन के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए इंग्लैंड में एक समिति नियुक्त की; समिति ने सलाह दी कि इंग्लैंड के सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय के परंपरा का पालन भारत सरकार द्वारा राज्य दस्तावेजों के संबंध में किया जाना चाहिए। (राज्य सचिव से भारत सरकार के लिए प्रेषण, संख्या 30, 31 मई 1888)। इस बीच फरवरी 1888 में वाइसराय डफरीन के अधीन भारत सरकार ने रिकॉर्ड प्रकाशन योजना के पुनरुत्थान का विरोध किया। इस संयुक्त पहल का नतीजा लंदन, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में रिकॉर्ड की प्रेस सूचियां तैयार करने और उसके बाद दस्तावेजों के कैलेंडर शुरू करने की योजना थी। यही वह समय है जहां मामला 1888 में ठहर सा गया था।

नीति विकल्प और 1891 में निर्णय

(2) दूरदर्शिता में जब हम इस अवधि पर पीछे देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इस विचार में एक झूठा द्विभाजन था कि लिस्टिंग और कैलेंडरिंग और अभिलेखों का प्रकाशन म्यूनिमेंट कार्यालय या केंद्रीय

रिकॉर्ड कार्यालय के निर्माण का एक विकल्प था। लिस्टिंग और कैलेंडरिंग का कार्य करने हेतु बार-बार राज्य सचिव (और उनके सलाहकार, इंग्लैंड में मास्टर ऑफ रोल्ल्स) द्वारा अनुरोध किया गया था और भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन बहुत कम कार्य किया गया था क्योंकि उन कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय की तरह कोई एजेंसी नहीं थी। हालांकि, 1889 तक इस तथ्य को बेहतर नीति निर्माताओं जैसे राज्य सचिव और वाइसराय और उनकी परिषद में उच्च रैंकिंग सिविल सर्वन्ट द्वारा नहीं माना गया था। 1989 में लगभग संयोग से भारत सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति की पहचान की जिस पर केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए या इसकी ओर अग्रसर होने वाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। इस प्रकार निर्धारित किए गए व्यक्ति जी. डब्ल्यू. फोरेस्ट थे, जो भविष्य में इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफिस के प्रमुख होने वाले थे; कार्रवाई की इस दिशा का अनकहा आधार सर विलियम हंटर द्वारा अनुशंसित नीति को त्यागना था और केंद्रीय रिकॉर्ड रूम की स्थापना से बचने के लिए 1872 में वाइसराय नॉर्थब्रुक की सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। फोरेस्ट बॉम्बे एजुकेशनल सर्विस में एक स्कूल शिक्षक थे जिन्होंने 1885 में बॉम्बे सरकार के दस्तावेजों के संकलन के बाद प्रतिष्ठा हासिल की थी। 1888 में उन्हें बॉम्बे सरकार ने उनके रिकॉर्ड को उचित क्रम में रखने के लिए नियुक्त किया था जो लापरवाही के कारण एक अव्यवस्थित स्थिति में था। 1889 में बॉम्बे सरकार ने "नए रिकॉर्ड ऑफिस में सरकारी रिकॉर्ड की व्यवस्था और वर्गीकरण में [फोरेस्ट द्वारा] हुई प्रगति" के मूल्यांकन को रिकॉर्ड करने का संकल्प किया। (बॉम्बे सरकार संकल्प संख्या 4964, 30 नवंबर 1889, सामान्य विभाग, भारत सरकार में, सार्वजनिक, मार्च 1891, संख्या 24- 42)। बॉम्बे प्रेसीडेंसी में एक अधीनस्थ सरकार द्वारा नए रिकॉर्ड ऑफिस के निर्माण के साथ-साथ राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस के दबाव का जवाब देने की तत्काल आवश्यकता के कारण संभवतः भारत सरकार को अपने स्वयं के केंद्रीय रिकॉर्ड ऑफिस स्थापित करने का निर्देशन किया। फोरेस्ट, 45 वर्ष का अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति (और 750 रुपये - 1000 रुपये के निम्न ग्रेड में एक शिक्षक) को भारतीय सरकार द्वारा विदेशी विभाग के रिकॉर्ड को उचित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना गया था। उनका काम संतोषजनक पाया गया था और भारत सरकार उनके वादे से प्रभावित थी कि, यदि उन्हें कार्यालय और भवन दिया जाएगा तो वह भारत सरकार का "एक रिकॉर्ड ऑफिस" बनाएंगे जो यूरोप में किसी भी रिकॉर्ड ऑफिस के साथ रैंक में बराबरी करेगा। (गृह, सार्वजनिक, मार्च 1891, संख्या 24-42, पृष्ठ 16)। इसके बाद भारत सरकार ने राज्य सचिव को भेजे गए प्रेषण में इस तरह के केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय की आवश्यकता पर बल दिया, "रिकॉर्ड की विस्तीर्णता पर ध्यान आकर्षित किया, जिन्हें [संबंधित विभागों में] उदासीनता से रखा गया हो जिन्हें शायद ही कभी परामर्श दिया जाता है और जो इस जलवायु में नमी और कीड़ों के संपर्क में आने के परिणामस्वरूप, तेजी से क्षय अधीन की समस्या हैं" जब तक ठीक से संरक्षित नहीं किए जाते हैं। (ईबीड, पृष्ठ 98)। नतीजतन, राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस ने "भारत सरकार के रिकॉर्ड्स के प्रभारी अधिकारी" पद के निर्माण को मंजूरी दे दी और जी.डब्ल्यू. फोरेस्ट इस प्रकार मार्च 1891 में भारत सरकार के रिकॉर्ड ऑफिस के संस्थापक प्रमुख बने।

अभिलेखीय रिकॉर्ड की उपयोगिता: सरकार के उद्देश्य

(3) जब तक हम सरकार के एजेंडा या उद्देश्यों पर विचार नहीं करते हैं तब तक अभिलेखीय नीति की कोई चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। पिछले पूर्व निर्णयों के आधार पर नीतियां और कार्यप्रणालियों का निर्माण करने की सरकार को अक्सर जरूरत महसूस होती है, इसके कारण पुराने रिकॉर्ड सरकार के लिए मूल्यवान थे। पत्राचार से यह देखना दिलचस्प है कि निचले स्तर पर प्रशासक अपने विभागों में ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधिक्य से इस पर कार्य करने के लिए अधीर थे, (गृह, सार्वजनिक, अक्टूबर 1899, संख्या 227-28), इनमें शीर्ष पर नीति निर्माता, उदा. वाइसराय काउंसिल के सचिव, पुराने रिकॉर्ड पर कार्य करने के लिए इच्छुक थे। बाद में 1889 में राज्य के सचिव को उनके प्रेषण में लिखा गया था: पुराने रिकॉर्ड को "एक स्थिति जिसमें वे समय के विध्वंस का प्रतिरोध कर सकते हैं, और वर्तमान मामलों की चर्चा में संदर्भ के लिए अपनी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए" रखा जाना चाहिए। (गृह, पब्लिक, मार्च 1891, संख्या 24 - 42, पृष्ठ 98; प्रभाव से जोड़ा गया)। नौकरशाहों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, विदेश विभाग के उनके रिकॉर्ड थे क्योंकि अफगानिस्तान से मणिपुर और कश्मीर से त्रावणकोर तक सैकड़ों मूल रियासतों और सरदारों के साथ संबंधों को कई समझौतों और प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया गया था, जो 18 वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में वापस चला गया। इसके अलावा ब्रिटिश भारत के सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध समझौते के अनुसार निर्धारित किए गए थे। (यहां तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय में भी भारत सरकार को इन संग्रहीत डेटा को मैकमोहन लाइन के आमने-सामने, या हिमालय पर या उससे बाहर के राज्यों के साथ भारत के संबंधों में अपनी स्थिति की रक्षा करने की दृष्टि से इसका मुहायना करते देखा गया है)।

दूसरे स्थान में, गृह विभाग में यह दस्तावेज आंतरिक प्रशासन के संबंध में पूर्व निर्णय और समझौता के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत में आदिवासी समूहों के साथ कैसे पेश आए? स्थानीय कुलीन और जमींदार कौन थे? अतीत में उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान जो अंग्रेजों के लिए विश्वसनीय सहयोगी थे,? ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए जातीय समूह कौन से थे? अतीत में खतरनाक राष्ट्रवादी आंदोलक या समूह कौन से थे? इन सवालों को रिकॉर्ड के संदर्भ में सुलझाया गया था। कुछ अन्य मामलों में भी प्रशासकों द्वारा रिकॉर्ड से परामर्श लिया गया था। इस आवश्यकता का सबसे जबरदस्त उदाहरण स्थायी निपटारे के बाहर के क्षेत्रों में भूमि राजस्व मांग का आवधिक मूल्यांकन था; राजस्व मांग में वृद्धि के लिए उत्पादन में वृद्धि का आकलन करने के लिए फसल काटने या 'आंखों से किया गया- प्राक्कलन कार्य' आदि जैसे अन्य साधन थे, लेकिन आम तौर पर अंगूठे का नियम यह पता लगाने के लिए किया गया था कि 20 से 30 साल पहले पिछले राजस्व निपटारे के संचालन में मूल्यांकन क्या था, और इसे एक निश्चित प्रतिशत तक जैक करने के लिए किया गया था। इस प्रकार जिला कलेक्टर को पुरानी राजस्व निपटारे के अभिलेखों तक पहुंचना एक अनिवार्य आवश्यकता थी। (बीएच बाडेन-पॉवेल, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑक्सफोर्ड, 1892, वॉल्यूम I -III; पुनर्मुद्रण

1972)। इसके अलावा, यह राजस्व, वाणिज्य, जनसंख्या, शिक्षा इत्यादि के रिकॉर्ड और आंकड़ों के अनुरक्षण के लिए एक वैधानिक दायित्व था। चूंकि क्राउन प्रशासन ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर कब्जा कर लिया था, इसलिए ब्रिटिश संसद में भारत सरकार को नैतिक और भौतिक प्रगति पर समय-समय पर रिपोर्ट जमा करना अपेक्षित था, जिसमें रिकॉर्ड से एकत्रित इन आंकड़ों को शामिल किया गया था।

उपर्युक्त कारण जो व्यावहारिक थे, के अलावा, अभिलेखागार के संभाषण में वैचारिक तत्व भी थे। पूर्व निर्णयों का सम्मान ब्रिटिशों की राजनीतिक संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। विभिन्न प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई के पिछले रिकॉर्ड के आवश्यक संदर्भ, पूर्व निर्णयों और समझौते पर अपेक्षित कार्रवाई करने के आधार पर ही उनकी सोचने की प्रवृत्ति का अधिष्ठान किया गया था। दूसरा, इतिहास में अपनी जगह सुरक्षित करने की इच्छा और भावी पीढ़ी के प्रतिकूल फैसले लेने से खुद को बचाने की इच्छा में एक और विचारधारात्मक तत्व था। इस ऐतिहासिक चेतना को औपनिवेशिक इतिहासलेखन- ब्रिटिश भारत का इतिहास जेम्स मिल के बाद मौनस्टुआर्ट एल्फिंस्टन, जे.टी.हेलर, अल्फ्रेड लाइल और अन्य के कार्यों द्वारा आगे बढ़ाया गया था। सर एच.एच. रिस्ले के टिप्पणी में हम पहले ही ब्रिटिश शासन की राष्ट्रवादी आलोचना के बारे में जागरूकता देखते हैं: उदाहरण के लिए वह एक प्रमुख राष्ट्रवादी पत्रकार एन. एन. घोष के ऐतिहासिक कार्य को संदर्भित करते हैं जिन्होंने नबकिसेन (नवकृष्ण) द दीवान ऑफ लार्ड कलाइव, पर एक पुस्तक में कुछ प्रकाशित सरकारी रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया; इसलिए रिस्ले ने अभिलेखागार में नियम की अभिलाषा की है जो "बेईमान छात्रों को रिकॉर्ड के उन हिस्सों को चुनने और प्रकाशित करने से रोक देगा जो उनके दृष्टिकोण के पक्ष में कहते हैं"। (23 जून 1904, एच. एच. रिस्ले की टिप्पणी, होम, पब्लिक, सितंबर, 1904, संख्या 98, पृष्ठ 12)। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि लॉर्ड कर्ज़न जैसे उच्च स्तर पर नीति निर्माता, जिसका रिस्ले ने इंपीरियल रिकॉर्ड में "बेहद दिलचस्पी" के रूप में उल्लेख किया है, इस दृष्टिकोण को साझा किया है। इन सभी कारणों से यह नीतिगत-स्तर की सोच के लिए अभिलेखों का उचित संग्रहण महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि ब्रिटिश राज्यकर्ताओं ने भारत सरकार को एक महान साम्राज्य के लिए अभिलेखीत करने का उपयुक्त तरीका खुद को लागू करने का कई बार आग्रह किया है। सर चार्ल्स वुड से लॉर्ड क्रॉस तक राज्य सचिवों की एक श्रृंखला ने उस उद्देश्य के गंभीरता और महत्व की भारत सरकार को याद दिलायी; शायद वे उसके महत्व के बारे में अधिक जागरूक थे क्योंकि वे संसद और कैबिनेट के सदस्य के रूप में, भारत सरकार में औसत नौकरशाहों के विपरीत राजनीतिक व्यक्ति थे।

चरण III : 1891-1911

इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग की स्थापना मार्च 1891 में हुई थी और 1911 में दिल्ली में राजधानी के स्थानांतरण के साथ एक युग समाप्त हो गया था। चरण 1891-1904 में नव निर्मित इंपीरियल रिकॉर्ड्स

विभाग में विभाग के प्रमुख प्रतिष्ठित अधिकारियों की एक श्रृंखला थी: विभाग के संस्थापक जी. डब्ल्यू. फोरेस्ट, 1891 -1900 में; सिराजुद्दुल्लाह और प्लासी की लड़ाई की अवधि का एक प्रतिष्ठित इतिहासकार, एस. सी. हिल 1900 - 1902 में; और 1902 -1904 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पुरातात्विक इतिहासकार सी.आर. विल्सन। विल्सन प्रतिष्ठित इतिहासकार थे और उन्होंने द एनल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल के रिकॉर्डों का व्यापक रूप से पढ़ा गया संकलन प्रकाशित किया। उनके बाद संक्षिप्त अवधि के लिए एक अधिकारी एन.एल. हॉलवर्ड, 1904 - 1905 में, और 1905 - 14 में एक प्रसिद्ध फारसी विशेषज्ञ ई. डेनिस रॉस नियुक्त किए गए। यद्यपि यह चरण 1911 में कलकत्ता से दिल्ली तक राजधानी के स्थानांतरण के साथ खत्म हो गया, कलकत्ता से रिकॉर्ड के वास्तविक पुनः स्थानापन्न करने में काफी समय लगा, क्योंकि क्वीन्स वे (जन पथ) पर इमारत के निर्माण की प्रतीक्षा की गई थी, निर्माण कार्य 1926 में पूरा हो गया था।

रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख का पदनाम:

विभाग के प्रमुख को मूल रूप से 1891 में 'रिकॉर्ड्स के प्रभारी अधिकारी' कहा जाता था और हम समकालीन फाइलों में देख सकते हैं और उन्हें 'ओआर' के रूप में संदर्भित किया गया है। (उदाहरण के लिए गृह (सार्वजनिक) में 1896 के लगभग 50 ज्ञापनों का एक सेट, अक्टूबर 1899, सं. 227 - 228)। सी.आर. विल्सन ने केवल एक सहायक सचिव के बराबर रैंक में उस पद पर अधिभार ग्रहण कर लिया था। 1904 में उन्होंने गृह विभाग के सचिव को एक आधिकारिक नोट में लिखा था: "ऐसा लगता है कि भारत सरकार के रिकॉर्ड्स के प्रभारी अधिकारी शीर्षक बहुत लंबा और बोझिल है ... श्री. फोरेस्ट खुद को 'इंपीरियल रिकॉर्ड्स के निदेशक' या इस तरह का कुछ कहते थे ... मुझे ऐसा लगता है कि यह अर्थहीन है। मैं कैसे रिकॉर्ड निर्देशित कर सकता हूँ? रिकॉर्ड निर्देशों का क्या मतलब है? 'इंपीरियल आर्किविस्ट' काफी छोटा है लेकिन शब्द अजीब और विदेशी लगता है। शायद सबसे अच्छा खिताब 'कीपर ऑफ इंपीरियल आर्काइव्स' होगा..... मैंने सरकार का इस बिंदु पर ध्यानाकर्षित किया है, और वे कुछ छोटे और संभावित शीर्षक के बारे में सोचेंगे।" (इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफिस पर सी.आर. विल्सन टिप्पणी, 21.5.1904, होम, पब्लिक ब्रांच, सितंबर 1904, संख्या 98)। सरकार ने किया और 1944 तक पदनाम 'कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स' के रूप में जाना जाने लगा। (1944 में उन्हें निदेशक अभिलेखागार के रूप में फिर से नामित किया गया, यह तब हुआ जब प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. सुरेंद्र नाथ सेन इस कार्यालय में थे। 30 अगस्त 1947 को विभाग को फिर से राष्ट्रीय अभिलेखागार का नाम दिया गया)।

1891 में रिकॉर्ड विभाग की स्थापना वर्षों में महत्वपूर्ण विकास और नीतिगत रुझान निम्नानुसार थे:

रिकॉर्ड विभाग का कार्यक्रम:

(1) विभाग के पहले प्रमुख जी.डब्ल्यू.फोरेस्ट ने जीओआई को पुराने दस्तावेजों की अनुसूची और प्रेस सूचियों को तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और अनुमोदन प्राप्ति पर 'कार्यवाही वॉल्यूम'

और 'मूल संग्रह' पर कार्य शुरू हुआ। 3 जून 1897 के अपने प्रेषण में भारत के राज्य सचिव ने निर्देश दिया कि प्रेस सूची भारत में तैयार की जानी चाहिए, दस्तावेजों के कैलेंडर इंग्लैंड में तैयार किए जाने थे; इसके अतिरिक्त, भारत सरकार "कभी-कभी अभिलेखों के आधार पर आधिकारिक प्रकाशनों के संकलन को मंजूरी दे सकती है"। (होम, पब्लिक, अक्टूबर 1896, संख्या 200 - 08; अप्रैल 1897, संख्या 220 - 28)। चूंकि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इंग्लैंड में कैलेंडरिंग कार्य छोड़ दिया गया था और 1903 से इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग में भारत में कैलेंडरिंग कार्य शुरू किया गया था। (होम पब्लिक, अप्रैल 1903, संख्या 47-48; 25 मई 1904 की आर. नाथन की टिप्पणी, होम, पब्लिक, सितंबर 1904, संख्या 98)।

अंग्रेजी मॉडल

(2) कुल मिलाकर से अंग्रेजी मॉडल और प्रक्रियाओं को देखने की एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति साथ ही देशी भारतीय कर्मचारियों में विश्वास की कमी भी है। इंग्लैंड में रोल्स के मास्टर के साथ-साथ अंग्रेजी रिकॉर्ड ऑफिस के प्रमुख, श्री मैक्सवेल लिट्टे से भारत सरकार द्वारा सलाह ली गई थी। हालांकि, इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग को नियंत्रित करते हुए तत्कालीन गृह सचिव सर हेनरी एच. रिस्ले के बयान के आधार पर ऐसा लगता है कि उन सलाहकारों की सलाह पर कार्रवाई नहीं की गई थी। (एच.एच. रिस्ले द्वारा ज्ञापन, 23 जुलाई 1904, गृह, सार्वजनिक, सितंबर 1904, संख्या 98)। रिस्ले लिखते हैं कि कैलेंडरिंग में संक्षेप लिखना शामिल है और विल्सन जैसे अंग्रेजी अधिकारी "एक देशी क्लर्क को एक संक्षेपिका मसौदा तयार करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं" लेकिन रिस्ले संदेहजनक था कि "क्या उनका कोई भी कर्मचारियों सक्षम है ... इनकी प्रवृत्ति सार के बजाय प्रतिलिपि तैयार करने की ही होगी, और जिस अनुपात में संपादक [अंग्रेजी अधिकारी] को अस्वीकार करना होगा या फिर से लिखना होगा, वह बहुत बड़ा होगा।" (रिस्ले, इबिद पैरा सं. 2)। देशी अधीनस्थों पर संदेह ने कैलेंडर की रिकॉर्डिंग और कैटलॉगिंग की सभी प्रक्रियाओं को धीमा कर दिया। हालांकि रिकॉर्ड्स विभाग के प्रमुख विल्सन ने इंग्लैंड के अभिलेखीय विशेषज्ञों की नियुक्ति की सिफारिश नहीं की थी, जिसकी गृह विभाग में उनके वरिष्ठ आर. नाथन और एच.एच. रिस्ले द्वारा दृढ़ता से वकालत की गई थी, जिनको लंदन में रिकॉर्ड ऑफिस में प्रशिक्षित "गृह नगर से एक अच्छा अधिकारी", यानी इंग्लैंड से, पाने की प्रभावकारिता में बहुत भरोसा था। (आर. नाथन, उप सचिव, गृह विभाग, द्वारा टिप्पणी 25 मई, 1904, गृह (सार्वजनिक) सितंबर, 1904, पृष्ठ 9)। हालांकि, आर्थिक तंगी और उपयुक्त कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण अन्य बातों के साथ, इस योजना पर भी कभी कार्य नहीं किया गया। व्यवस्थित प्रशिक्षण द्वारा समर्थित पेशे के रूप में संग्रह करना अभी तक विकसित नहीं हुआ था और इस प्रकार भारत में इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग, विभाग में प्रशिक्षित कर्मचारियों और उन अधिकारियों पर निर्भर करता था जिन्हें शिक्षाविदों या कुछ असाधारण सिविल नौकरियों से भर्ती कराया गया था, जिन्हें ऐतिहासिक रुची थी।

रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुंच को अस्वीकार करना:

(3) राजा के प्रति भारतीय निष्ठा के संबंध में संदेह सरकार के रिकॉर्ड तक भारतीय पहुंच को नकारने की नीति में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। यद्यपि एक पेशेवर इतिहासकार, सी.आर. विल्सन, इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग का नेतृत्व करते हुए आर. नाथन, उप सचिव, गृह विभाग को अनुमति देने के लिए तैयार थे, उन्होंने एक नीतिगत टिप्पणी में लिखा है कि "रिकॉर्ड में जनता को ऐसी मुफ्त पहुंच अनुमति देना जैसा कि मिस्टर विल्सन विचार करते प्रतीत होते हैं, यह शायद बहुत अवांछनीय माना जाएगा"। (आर. नाथन, फाइल नोटिंग दिनांक 25 मई 1904, गृह, सार्वजनिक, सितंबर, 1904, संख्या 98)। गृह विभाग के सचिव रिस्ले ने इस दृष्टिकोण के कारण दिए: "मैं लोगों को हमारे रिकॉर्ड में छानबीन करने की लिए छूट देने का पूरी तरह से विरोध करता हूं...मेरी राय में, ऐसी सामग्रियों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा होगा, इस प्रकार इसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से उपयोग किया जाएगा"। (इबीद, रिस्ले की टिप्पणी, 23 जून 1904)। रिस्ले ने सोचा कि रिकॉर्ड का एक चयनात्मक पढ़ना और उद्धरण खतरनाक था और यह बेहतर होगा अगर संपूर्ण रिकॉर्ड उद्धृत प्रकाशित रूप में उपलब्ध कराया गया हो। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, इस संबंध में ब्रिटिश भारतीय सरकार के दृष्टिकोण के कारण भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के आखिरी दशक तक अपने देश के इतिहास के अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त नहीं की थी। और अब तक भारत सरकार के नीति विवरण राज्य सचिव (1904 की संख्या 313, वित्त और वाणिज्य विभाग में, 1 सितंबर, 1904, गृह, सार्वजनिक, सितंबर 1904, संख्या 98) को उनके प्रेषण में कहा कि यह अफसोस की बात है कि "हम पाते हैं कि वर्तमान समय तक छात्रों के लिए सुलभ रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बहुत कम काम किया गया है" और भारत सरकार सक्रिय रूप से "शोध के लिए जनता को दी गई सुविधाओं के सवाल" पर विचार कर रही थी। इस चिंता के बीच असंगतता और ऊपर उद्धृत रिस्ले के नीतिगत वक्तव्य में केवल एक स्पष्टीकरण हो सकता है: लंदन को उनके प्रेषण में भारत सरकार ने जिन इतिहास और शोधकर्ताओं के छात्रों का उल्लेख किया वे भारतीय नहीं बल्कि यूरोपीय थे। प्रेस सूचियों और कैलेंडर तैयार करने के लिए और उचित क्रम में रिकॉर्ड रखने के लिए यह कार्यक्रम विदेशी शोधकर्ताओं की सहायता के लिए था, भारतीयों को उस विशेषाधिकार से बाहर रखा गया था।

रिकॉर्ड विभाग का स्थानांतरण:

1896 में कलकत्ता और सिमला, राजधानी शहरों में जहां भारत सरकार ने कार्य किया था पुराने रिकॉर्ड के संचय की समस्या के बारे में गृह विभाग, सार्वजनिक, शाखा में परामर्श की एक श्रृंखला अस्तित्व में आयी। चूंकि सचिवों में से एक ने कहा है: "प्राचीन अभिलेखों की विशाल फाइलें हैं जिन्हें रखा जाना चाहिए लेकिन व्यावहारिक रूप से इसे कभी संदर्भित नहीं किया जाता है, और हो सकता है इसे थोड़ी सी असुविधा के बिना उपनगरों में पर्याप्त लेकिन सस्ती इमारतों में, रखा जाना चाहिए। वर्तमान में हमारे पास उन्हें रखने के लिए कहीं भी नहीं बल्कि कलकत्ता कार्यालयों में प्रदान की जाने वाली बहुमूल्य जगह है।" (जे वेस्टलैंड, जापन दिनांक 6 मार्च 1896, लोक निर्माण विभाग, गृह (सार्वजनिक), अक्टूबर 1896, संख्या 227)। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने उपनगरों में उपयुक्त इमारत के निर्माण तथा जो रिकॉर्ड अब

सक्रिय उपयोग में नहीं है के "देखभाल के लिए एक कम व्यय वाले विभाग का निर्माण" करने का प्रस्ताव दिया। इस समय अन्य विभागों में सचिव जगह बचाने के लिए महत्वहीन (पार्ट-बी पेपर) को नष्ट करने के सशक्त उपायों पर विचार कर रहे थे। (गृह (सार्वजनिक), अक्टूबर 1899, संख्या 227 में 6-3-1896 से 8-6-1896 के बीच पत्राचार देखें)।

उपर्युक्त चर्चाओं के अनुसार और जी.डब्ल्यू. फॉरेस्ट, रिकॉर्ड विभाग के परामर्श से, जनवरी 1897 में लोक निर्माण विभाग द्वारा एक योजना बनाई गई, "पुराने रिकॉर्ड के भंडारण के लिए कलकत्ता के उपनगरों में इमारतों के निर्माण" के साथ-साथ "बेकार रिकॉर्डों को कम करने और नष्ट करने का प्रस्ताव"। प्रस्ताव दो विभागों को छोड़कर केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय बनाने की दिशा में "आंशिक कदम" उठाना था क्योंकि "सैन्य और विदेशी विभाग रिकॉर्ड भेजे जाने के इच्छुक नहीं होंगे"। तब अनुमान लगाया गया कि केवल गृह और लोक निर्माण विभाग को आठ हजार वर्ग फुट की आवश्यकता होगी और अन्य विभागों को प्रत्येकी आठ हजार वर्ग फुट की आवश्यकता होगी। (लोक निर्माण विभाग से अनौपचारिक ज्ञापन ,जीओआई, संख्या 21, जनवरी 1897, गृह (सार्वजनिक), अक्टूबर 1899, संख्या 227- 28)। तथापि, दूरी की वजह से जब आवश्यक हो, रिकॉर्ड प्राप्त करने की असुविधा साथ ही जी.डब्ल्यू. फॉरेस्ट की केंद्रीय कलकत्ता से उपनगरों में जाने की अनिच्छा यह बाधाएं थीं और इस प्रकार 1911 में कलकत्ता से नई दिल्ली तक राजधानी के स्थानांतरण के लिए रिकॉर्ड के लिए कोई विशेष इमारत नहीं बनाई गई थी, या अधिक सटीक रूप से, 1926 में वर्तमान एनएआई भवन का निर्माण।

निष्कर्ष:

वर्तमान चरण 1891 - 1911, के अंत में, इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग कलकत्ता में महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के परिवार का एक उपेक्षित विभाग था। विभाग का प्रमुख केवल सहायक सचिव के बराबर रैंक का था, जिसकी कलकत्ता में डलहौसी स्क्वायर में सचिवालय के परिसर में एक अस्थायी और अनिश्चित अधिकार था, और उसके कर्मचारियों की संख्या 100 से कम थी। (सी.आर. विल्सन, भारत सरकार के रिकॉर्ड्स के प्रभारी अधिकारी, गृह विभाग, 20 मई 1904, और इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग पर वार्षिक रिपोर्ट, गृह, सार्वजनिक, सितंबर 1904, संख्या 98, पीपी 12 - 15)। हालांकि, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, इस चरण के बाद की अवधि में, राजधानी के साथ नई दिल्ली में एक केंद्रीय स्थान पर कार्यालय के स्थानांतरण (1911 - 1926), इंग्लैंड में रॉयल कमीशन ऑफ रिकॉर्ड्स (1914) की रिपोर्ट में भारतीय रिकॉर्ड के संबंध में सिफारिशें, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग की नियुक्ति (1919) और राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान राजनीतिक माहौल को गर्म करने के कारण, इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग ने महत्व हासिल करना शुरू कर दिया। यह परियोजना के कार्य के अगले चरण का विषय बन जाएगा।

सबासाची भट्टाचार्य

परियोजना कार्य, जुलाई 2013 से दिसंबर 2013 की तीसरी रिपोर्ट

परियोजना का शीर्षक: औपनिवेशिक अभिलेखीय नीति, 1858 - 1947

द्वारा

सबासाची भट्टाचार्य

इस परियोजना पर मेरे द्वारा पिछली रिपोर्टों की अवधि 1858 से 1872 (रिपोर्ट संख्या I), और 1872 से 1911 (रिपोर्ट संख्या II) शामिल थी। वर्तमान रिपोर्ट 1911 से 1926 की अवधि से संबंधित है।

इस अवधि में जिन प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया जा रहा है वे निम्नलिखित हैं:

- (1) 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित करने के लिए नीतिगत निर्णय की घोषणा;
- (2) सर एडविन लुटियंस द्वारा योजनाबद्ध नई दिल्ली में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग (अब एनएआई भवन) के लिए एक इमारत का निर्माण कार्य, और 1926 में इसे पूरा किया गया;
- (3) कलकत्ता से इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग का स्थानांतरण नई दिल्ली में नई इमारत में (नवंबर 1926) और भारत सरकार के रिकॉर्ड का विभाजन पूरा किया गया उनसे जो बंगाल सरकार के पास थे;
- (4) इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग में विकास की कार्यवाही और इंग्लैंड (1914) में सार्वजनिक अभिलेखों पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के नीतिगत प्रभाव;
- (5) इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग (1925) में, इंपीरियल नौकरशाही के लंबे समय से चल रहे विरोध के खिलाफ गैर-अधिकारियों और मूल भारतीयों को ऐसे रिकॉर्ड तक पहुंचने की इजाजत देने के लिए ऐतिहासिक अभिलेखों के शोधकर्ताओं के पहुंच हेतु खुला करना;
- (6) भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग (1919) का गठन, जिससे विशेषज्ञों और इतिहासकारों को अभिलेखागार पर सरकार के सलाहकारों की भूमिका में शामिल किया गया।

मैं निम्नलिखित पृष्ठों में उपरोक्त के रूप से अपने निष्कर्षों को क्रमशः जोड़ने की कोशिश करूंगा।

1. कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का नीतिगत निर्णय, 1911, और

परिणामी कार्रवाई।

कलकत्ता से दिल्ली तक राजधानी के स्थानांतरण का स्पष्ट रूप से मतलब था कलकत्ता से नई दिल्ली तक इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग (इसके बाद आईआर विभाग) का स्थानांतरण। 25 अगस्त 1911 को

गवर्नर जनरल इन कौंसिल ने लंदन में भारत के विदेश सचिव को लिखा: "भारत सरकार के मुख्य प्रांतीय सरकारों में से एक की इसी शहर में अपनी सीट होनी चाहिए, और इसके अलावा कलकत्ता जैसे भूगर्भीय रूप से इतने खराब शहर में भारतीय साम्राज्य की राजधानी होना लंबे समय से एक गंभीर विसंगति माना जाता है। विभाजन के बाद से बंगाल में पैदा हुई असाधारण राजनीतिक स्थिति ने भारत में अपने वर्तमान प्रांतीय परिस्थिति से सरकार को इसे वापस लेने के लिए बेहद वांछनीय बना दिया है, जबकि बंगाल से इसे हटाने की योजना की एक आवश्यक विशेषता है, बंगाली आबादी के बीच हुए विभाजन से उत्पन्न परिस्थिति से हमने इसको अस्वस्थ महसूस करते देखा है। भौगोलिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक आधार पर, भारतीय साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में होनी चाहिए, और सरकार की दिल्ली की सीट के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी गई है इसकी घोषणा दिल्ली में होने वाले इंपीरियल दरबार में महामहिम महाराजाधिराज, द्वारा की जानी चाहिए ... बेशक, प्रस्ताव को अनुकूल तरीके से निपटाया जा सकता है, बंगाली शायद नहीं मानेंगे, अगर यह अकेला प्रस्ताव होगा, इसके लिए कुछ प्रभावों का नुकसान होगा, जिसे वे अब इस तथ्य के कारण अपनाते हैं कि कलकत्ता भारत सरकार का मुख्यालय है। लेकिन, जैसा कि हम वर्तमान में आशा करते हैं, उन्हें हमारी योजना की अन्य विशेषताओं के बदलाव से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिन्हें बंगाली भावनाओं को संतुष्टि देने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। " वह अन्य विशेषता बंगाल के विभाजन (1905) को रद्द करना था जिसके खिलाफ कई वर्षों तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन बढ़ गया। इंग्लैंड में राजधानी का स्थानांतरण और बंगाल के विभाजन को रद्द करने की काफी आलोचना हुई थी, उदाहरण के लिए संसद में बहस के दौरान, हंसर्ड की रिपोर्ट में, लॉर्ड कर्जन बहुत टिकात्मक थे: "मुझे यह कहने का साहस हुआ है कि राज्य सचिव मुझे यह कहकर सांतवना देने का प्रयास करेगा कि विभाजन रद्द नहीं किया गया है। लेकिन सभी प्रयोजन और उद्देश्यों के लिए पुराने विभाजन को बदल दिया गया है। शायद क्या विभाजन को बदल दिया गया है या नहीं इसका सबसे अच्छा, निर्णय भारत में खुद मिल जाएगा। दिल्ली में घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस कमेटी ने राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार को धन्यवाद दिया और इसे पारित किया; और बाद में, कांग्रेस की बैठक में, राष्ट्रपति ने आधुनिक समय में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संघर्ष में जीत के रूप में विभाजन की समाप्ति की बात की। भारत के किसी भी हिस्से में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आंदोलन की विजय हुई है। "हालांकि, महाराजाधिराज द्वारा एक बार लिया गया निर्णय और की गई घोषणा, अपरिवर्तनीय थी। इसकी परिणामी कार्रवाई, कलकत्ता में इंपीरियल सचिवालय से भारत सरकार के विभागों को नई राजधानी में नए स्थान पर स्थानांतरित करने की विशाल प्रक्रिया की शुरुआत थी। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग जो 1891 में विभाग की स्थापना से इंपीरियल सचिवालय (आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों से राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है) में स्थित था, ने स्थानांतरण के लिए रिकॉर्ड व्यवस्थित करना शुरू किया। उस समय कीपर ऑफ इंपीरियल रिकॉर्ड्स ई. डेनिस रॉस थे।

2. इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग भवन (वर्तमान में एनएआई) 1912 - 1926 का निर्माण

1911 में राजधानी को स्थानांतरित करने का स्पष्ट नतीजा रिकॉर्ड रूम का स्थानांतरण था, लेकिन नई दिल्ली में इसे कहाँ रखा जाएगा? 1912 में दो बातें हुई जिन्होंने उस प्रश्न का फैसला किया। सबसे पहले, वाइसराय हार्डिंग जो राजधानी को स्थानांतरित करने के विचार के प्रमुख समर्थक थे, 12 अक्टूबर, 1912 को एक ज्ञापन में प्रस्तावित किया कि एक इमारत का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें "वर्तमान वर्षों के रिकॉर्ड को छोड़कर भारत सरकार के सभी अभिलेखों को रखा जाना चाहिए, जो संबंधित विभागों के पास छोड़ा जाएगा और विस्तार हेतु प्रदान किया जाएगा।" (वाइसराय हार्डिंग, गृह विभाग सार्वजनिक शाखा द्वारा कार्यवृत्त, डिपॉजिट, जनवरी 1914, संख्या 27, पृष्ठ 45)। इसने इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के पिछले अनुभव पर एक बड़ा सुधार करने का वादा किया- यह 1891 में अपनी स्थापना के बाद कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग के एक छोटे से कोने में था। दूसरा, नई दिल्ली के बारे में एक व्यापक दृष्टि रखने वाला एक आदमी सामने आया। नई दिल्ली योजना आयोग का नेतृत्व करने के लिए 43 वर्ष की आयु के अपेक्षाकृत जूनियर वास्तुकार एडविन लुटियंस को नियुक्त किया गया था; वह कभी भी किसी भी स्कूल या विश्वविद्यालय में नहीं गया था लेकिन उन्होंने कई कुलीन परिवारों के लिए घरों का डिजाइन किया था। उन्होंने भारत के पूर्व वाइसराय, लॉर्ड लिट्टन की पुत्री एमिली बुलवार-लिट्टन से विवाह किया था और इस प्रकार उनके भारत और इंग्लैंड के उच्चतम मंडलियों में दोस्त थे। लगता है कि लुटियंस अभिलेखागार के ऐतिहासिक महत्व से अवगत हैं और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसके लिए प्रचीन स्तंभों को लगाने के साथ ही लाल रेत पत्थर की एक इमारत की योजना बनाई। इमारत को मूल रूप से होलो स्केअर की तरह होने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वास्तव में केवल एक बाजू ही पूरी हो गयी थी- वर्तमान में जन पथ के सामने खड़ी है। यद्यपि यह लुटियंस के इमारत के डिजाइन को पीछे छोड़कर अपने मूल डिजाइन से छोटी थी, लेकिन इसके स्थान ने उसके संकल्पना में इसके महत्व का संकेत दिया था; रिकॉर्ड विभाग की इमारत क्वीन्स वे (जनपथ) और किंग्स वे (राजपथ) के चौराहे पर स्थित थी। इस तथ्य को प्रतिबिंबित करना दिलचस्प है कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के लिए इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग या राष्ट्रीय अभिलेखागार के विकर्ण रूप से विपरीत दिशा में, एक समान स्थान चुना। किसी भी कीमत पर, इसका यह परिणाम था कि इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग पहली बार अपनी विशेष इमारत में स्थानांतरित करना था। इससे शायद इंपीरियल सरकार के अभिलेखागार के महत्व का एक नया अधिमूल्यन परिलक्षित होता है।

3. आईआरडी का स्थानांतरण और कागजातों का हस्तांतरण

कलकत्ता से नई दिल्ली तक राजधानी के स्थानांतरण का संपार्श्विक परिणाम नई दिल्ली में इंपीरियल रिकॉर्ड्स का स्थानांतरण किया गया था, ऐसा लगता है कि यह लंबे समय से चल रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार में मैंने इस हस्तांतरण से संबंधित कई फाइलें देखीं जिनमें

भारत सरकार के रिकॉर्ड से बंगाल प्रेसीडेंसी के रिकॉर्ड को अलग करना शामिल था। यह ऐसी फाइलें हैं जो इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के दावों और प्रांतीय सरकार के दावों के बीच कुछ कागजात के लिए अधिकार-क्षेत्र के संघर्ष की एक श्रृंखला को इंगित करती हैं, उदाहरण के लिए 1918 - 1919 में "ए.एफ. शॉल्फिल्ड, एम.ए, कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स , भारत सरकार और बंगाल सरकार के मुख्य सचिव" के बिच में विवाद। बाद के अधिकारी कुछ दस्तावेजों के संबंध में शॉल्फिल्ड के कार्यालय में कुछ कागजात स्थानांतरित करने के इच्छुक नहीं थे, इस आधार पर कि "किसी भी मामले में हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि वे हमसे [यानी बंगाल सरकार से] या इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग से ये संबंधित है या नहीं।" (बंगाल सरकार, राजनीतिक विभाग, रिकॉर्ड शाखा, फा सं. 4 आर/1922)। यह देखना दिलचस्प है कि रिकॉर्ड विभाग, प्रांतीय और इंपीरियल यानी सेंट्रल, नेटिव क्लर्कों, 'सतीस बाबू' और 'हरि बाबू' पर भारी निर्भर था और जैसे कि खोज हेतु और वर्गीकरण और सूची रिकॉर्ड करने हेतु।

बंगाल सरकार से जीओआई इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग में रिकॉर्ड के हस्तांतरण ने एक विशाल पत्राचार उत्पन्न करना जारी रखा (उदाहरण के लिए बंगाल सरकार, राजनीतिक विभाग, रिकॉर्ड्स शाखा, बी, अगस्त 1920, संख्या 56-60; फा. संख्या 7 डी / 1920, शाही रिकॉर्ड विभाग के लिए, 1780 और 1834 के बीच के पंजीकृत कार्यों, महानिरीक्षक, पंजीकरण, कलकत्ता के अभिलेखों का पुनः हस्तांतरण; बंगाल सरकार, केडब्ल्यू फाइल जीआर / टी / 1922, संख्या 12-34; बंगाल सरकार, राजनीतिक विभाग, रिकॉर्ड्स शाखा, फा. नं. 72/1922, सत्तान्तरित और विजय प्राप्त प्रांतों के निदेशक, आयुक्त बोर्ड, बिहार और बनारस, राजस्व बोर्ड, एन.डब्ल्यू. प्रांत, और राजस्व बोर्ड, आईआर विभाग के लिए केंद्रीय प्रांत के अभिलेखों का पुनः हस्तांतरण। उपर्युक्त सभी रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार, कलकत्ता में हैं)। अभिलेखागार को विभाजित करने और बंगाल सरकार से इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग में रिकॉर्ड के हस्तांतरण में क्या शामिल था, यह दिखाने के लिए यहां एक सामान्य संप्रेषण का पुनरुत्पादन किया जा सकता है। यह उत्तरार्द्ध से भूतपूर्व को भेजा गया एक पत्र है: "यह कार्यालय [यानी आईआरडी, भारत सरकार] के पास केवल सार्वजनिक [विभाग] परामर्श का समूह है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्व और न्यायिक परामर्श से संबंधित सभी कागजात भारत सरकार के पास होने चाहिए "। (जे.एम. मित्रा, कीपर ऑफ रिकॉर्ड, भारत सरकार, इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग, से सचिव, बंगाल सरकार, राजनीतिक विभाग, 2 सितंबर, 1922, बंगाल सरकार, राजनीतिक (रिकॉर्ड शाखा), फा. संख्या 72/1922)। इसे समेकित करने हेतु, पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार, कलकत्ता के अभिलेखों में मेरा शोध, यह इंगित करता है कि वर्गीकरण और अभिलेखों को अलग करने की बहुत ही जटिल प्रक्रिया 1920 के दशक में इंपीरियल रिकॉर्ड और बंगाल सरकार के रिकॉर्ड को अलग करने के एक आवश्यक भाग के रूप में हुई है। यह एनएआई अभिलेखागार के क्रमिक विकास का एक हिस्सा था जैसा कि हम आज जानते हैं।

आईआर विभाग के कागजात को नई दिल्ली में स्थानांतरित करने के कार्य में 1926 में महत्वपूर्ण रूप से प्रगति हुई। ए.एफ.एम. अब्दुल अली, कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स, ने 1927 में रिपोर्ट की: "शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के पत्र में दिए गए आदेशों के अनुसार, सं. 1134 - जनरल, दिनांक 28 सितंबर 1926, क्राउन के रिकॉर्ड 1899 से आगे दो सहायक, 4 क्लर्क, 6 सॉर्टर्स और दफ्तरी, 3 चपरासी और 4 डिस्टिंग बेयरर्स इन कर्मचारी के साथ नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। नई दिल्ली में [नई इमारत में] रिकॉर्ड ऑफिस 1 नवंबर, 1926 को खोला गया था (ए.एफ.एम. अब्दुल अली सचिव, शिक्षा, 21 अप्रैल 1927, बंगाल सरकार, राजनीतिक (रिकॉर्ड्स) 2 आर/27)।

4. आईआरडी प्रशासन में विकास का क्रम, 1911 - 1926

समीक्षाधीन अवधि की शुरुआत में एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान ई. डेनिस रॉस किपर ऑफ इंपीरियल रेस्कॉर्ड्स थे। रॉस, 1905 से 1914 तक कार्यालय में थे, उनके पूर्ववर्तियों में सर जी. डब्ल्यू. फोरेस्ट (1891 - 1900), एस.सी. हिल (1900 - 1902) बंगाल के इतिहासकार और सी.आर. विल्सन (1902 - 1904) ईस्ट इंडिया कंपनी और कलकत्ता शहर के इतिहासकार और एन. एल. हॉलवर्ड (1904-1905) कार्यालय के अस्थायी प्रमुख थे। 1926 में जब कलकत्ता से नई दिल्ली में स्थानांतरण पूरा हो गया तो वहां प्रमुख ए.एफ.एम. अब्दुल अली थे। रॉस और अब्दुल अली, के बीच कुछ अपेक्षाकृत साधारण के कीपर ऑफ इंपीरियल रेस्कॉर्ड्स थे।

मैंने शाही रिकॉर्ड विभाग की विभागीय फाइलों में दस्तावेजों की जांच की है (जो फाइलें अब तक एनएआई में स्थानांतरित नहीं हुई हैं); ये केवल डीजी, एनएआई से विशेष अनुमति प्राप्त करने से सुलभ हुआ हैं, और मैंने विभागीय अभिलेखों से परामर्श करने की अनुमति प्राप्त की है। ये फाइलें मुख्य रूप से विभागीय प्रशासन के आंतरिक कार्य, उदाहरण के लिए विभिन्न विभागों से पुराने रिकॉर्ड का आईआरडी में स्थानांतरण (फरवरी 1909, संख्या 22, जुलाई 1916, संख्या 109); जिला कलेक्टरों में रिकॉर्ड के संरक्षण के संबंध में प्रांतीय सरकारों का अनुपालन (अगस्त 1910, संख्या 165); विशिष्ट अभिलेखों तक पहुंचने के लिए डब्ल्यू.के. फर्मिगर या रेव. एच. होस्टन जैसे कुछ व्यक्तियों को अनुमति (अक्टूबर 1908, संख्या -1-2-जून, 1912 संख्या 16); भारत में रिकॉर्ड पर विलियम फोस्टर की टिप्पणियां (अगस्त 1917, संख्या 65); आईआरडी के काम पर सी.आर. विल्सन की टिप्पणियां (मई 1903, संख्या 214); रिकॉर्ड से जानकारी प्रकाशित करने के आरोपी आईआरडी के क्लर्क के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई (मार्च 1904, संख्या 23) इत्यादि से संबंधित हैं। शोधकर्ताओं के अभिलेखों तक पहुंच के संबंध में एकमात्र महत्वपूर्ण फाइलें हैं जिन्हें 1914 में प्रस्तावित किया गया था और खारिज कर दिया गया था। (अप्रैल 1914, संख्या 53; दिसंबर 1914 संख्या 224)। बाकी फाइलें आम तौर पर प्रशासनिक दृष्टि से नगण्य विषयवस्तुओं के बारे में होती हैं, जो अभिलेखागार नीति से संबंधित नहीं हैं।

हालांकि, दो चीजें उल्लेखनीय हैं। सबसे पहले, कुल मिलाकर, आईआरडी एक छोटा सा विभाग था और 1930 के दशक तक बना रहा। इंग्लैंड में सार्वजनिक अभिलेखों पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट (1914) ने रिकॉर्ड संरक्षण के महत्व पर ध्यान दिया लेकिन उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की वजह से आर्थिक तंगी हुई। आईआरडी में नियुक्त बहुत छोटे कर्मचारियों से पता चलता है कि सरकार द्वारा इसे कोई बड़ा महत्व नहीं दिया गया था। पहले प्रमुख जॉर्ज फोरेस्ट ने बहुत कम कर्मचारियों से कार्य शुरू किया और 1892 में इन्हें स्थायी कर्मचारी बना दिया गया: उनमें केवल 5 क्लर्क, 4 दफ्तरी, और 8 अकुशल श्रमिक थे। (होम, पब्लिक ब्रांच, मार्च 1895 संख्या 130 - 135)। आईआर विभाग के अनुक्रमिक प्रमुखों और वित्त सचिव के बीच कर्मचारियों का विस्तार करने के अनुरोधों के साथ महत्वपूर्ण पत्राचार हुआ है। सी.आर. विल्सन ने शिकायत की कि आईआरडी "कर्मचारियों के लिए हमेशा अभिलाषी रहा है"। (सी.आर. विल्सन की टिप्पणी 27.04.04, होम (पब्लिक) सितंबर 1904, संख्या 98)। 1930 के दशक तक कम ही कर्मचारी रहे। दूसरा, हम अगले चरण में भी देखेंगे कि 1930 के दशक में एक दिलचस्प विकास हुआ था। विभिन्न सरकारी विभागों में रिकॉर्ड्स से संबंधित रोजगार का विस्तार, और विभिन्न जीओआई विभागों में निचले स्तर के कर्मचारियों यानी 'रिकॉर्ड सॉर्टर्स', 'रिकॉर्ड लिफ्टर्स' और दफ्तरीज के व्यापार संघीकरण, 'जीओआई गृह विभाग द्वारा मान्यता प्राप्ति' की ओर अग्रसर हुए हैं। (होम, पब्लिक ब्रांच, 1933 की फा. संख्या 16/1/33 का, सी.एफ.वी. विलियम, अवर सचिव, गृह विभाग से एस. हुसैन, "भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय रिकॉर्ड सॉर्टर्स, रिकॉर्ड लिफ्टर्स और दफ्तरीज एसोसिएशन" के सचिव, "4 जुलाई 1933)। ऐसा लगता है कि इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट स्टाफ उस एसोसिएशन में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने सरकारी विभागों में रिकॉर्ड श्रमिकों के ट्रेड यूनियनों के साथ वेतन वृद्धि आदि मांगने के लिए सरकार को अनुस्मारक दिया। (होम, एस्टेट्स शाखा (एस), फा. संख्या 48/18/45)। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि सभी गतिविधियां, जीएससी या सामान्य सेवा शर्तों द्वारा प्रतिबंधित थी, जो सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से वंचित करती थीं। (सीएफवी विलियम द्वारा टिप्पणी, 23.6.1933 ' जीएससी ' के संबंध में ऑडिटर जनरल के अवलोकन का हवाला देते हुए, इबीद.)।

5. अभिलेखागार को ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए खोलना

सरकार के अभिलेखागार खोलने के लिए नौकरशाहों का कड़ा विरोध था। जैसा कि मैंने अपनी परियोजना पर अपनी पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया था, पहले की अवधि में सर डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर ने गैर-आधिकारिक देशी भारतीयों के लिए रिकॉर्ड खोलने के विचार का विरोध किया था। उन्होंने सोचा कि यूरोप के सिवाय, भारत में अभिलेखागार का उपयोग करने में सक्षम "पात्र और समर्पित किस्म का कोई व्यक्ति नहीं था"; गृह सचिव ई. क्लाइव बेली ने 1872 में यह भी कहा कि "पिछले शताब्दी में भी ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसे जनता के लिए खुला करने से असुविधा [सरकार को] हो सकती हैं। (होम, पब्लिक ब्रांच, दिसंबर 1872 संख्या 647, 649)। 1871 जैसा 1904 में फिर से अभिलेखागार खोलने के लिए ऐसा ही

प्रतिरोध हुआ था। सर एच. एच. रिस्ले ने एन. एन. घोष के मामले की ओर इशारा किया, जिन्होंने नवकृष्ण, दीवान ऑफ कलाइव, पर एक पुस्तक में लिखा था, जिसमें ब्रिटिशों के प्रतिकूल प्रभाव को दिखाने के लिए प्रकाशित रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया; रिस्ले ने देखा कि अभिलेखागार खोलने का मतलब ब्रिटिश विरोधी प्रचार के उद्देश्यों से "इतिहास के विवेकहीन छात्रों" द्वारा रिकॉर्ड का दुरुपयोग होने की संभावना को खुला करना था। "मैं लोगों को हमारे रिकॉर्ड में छानबीन करने की लिए छूट देने का पूरी तरह से विरोध करता हूँ"। (एच.एच. रिस्ले, 23 जून 1904 दिनांक, गृह, सार्वजनिक, सितंबर 1904, संख्या 98, पृष्ठ 12)।

हालांकि, इंग्लैंड से ऐतिहासिक शोधकर्ताओं को भारतीय रिकॉर्ड तक पहुंचने की इजाजत देने का दबाव पड़ा। राज्य के एक से अधिक सचिव इस तरह की नीति चाहते थे और 1904 में भारत सरकार ने राज्य सचिव के समक्ष स्विकार किया कि अफसोस की बात है कि "छात्रों के लिए सुलभ रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बहुत कम कार्य किया गया है"। (राज्य सचिव को कलकत्ता में गवर्नर जनरल, 1 सितंबर 1904, गृह, सार्वजनिक, सितंबर 1904, संख्या 98)। फिर भी, स्थिति को बनाए रखा गया था, हालांकि सी.आर. विल्सन, कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स 1902 - 1904, अभिलेखागार खोलने के पक्ष में थे। 1914 में सार्वजनिक अभिलेखों पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन ने आखिरकार भारत सरकार के हाथों को मजबूर कर दिया। 1918 में सरकार ने लंबे समय तक रॉयल आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, इसे हल किया कि "वास्तविक छात्रों की रिकॉर्ड तक की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने थे"। (शिक्षा विभाग, जनरल-ए, अप्रैल 1918, फा सं. 1 -17)। 1919 में नियुक्त ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग के परामर्श से, भारत सरकार ने कुछ नियमों को तैयार किया जो ऐतिहासिक शोधकर्ताओं को कुछ शर्तों और निगरानी के तहत अभिलेखों तक पहुंचने की इजाजत देते हैं। नए नियम 1925 से लागू हो गए। (भारत सरकार के रिकॉर्ड्स हेतु हैंडबुक 1748 - 1858, परिशिष्ट)।

कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स से 1926 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया है कि कई शोधकर्ता थे जिन्होंने अभिलेखागार का उपयोग किया था। उनमें से निम्नलिखित इतिहासकार थे: आईसीएस के आर.बी. रामसबोधम, बॉम्बे के जी.एस. सरदेसाई, डेक्का विश्वविद्यालय के जे.सी. सिन्हा, कलकत्ता विश्वविद्यालय के जे.पी. नियोगी, विश्वविद्यालय कॉलेज, रंगून के ए.एस्पिनल, बंगाल साहित्यिक अकादमी या बांगिया साहित्य परिषद के बेंजेन्द्र नाथ बनर्जी, रंगून के जे. ई. हरवे, हैदराबाद के जी. यजादानी, पटना में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के खुदा बख्श, और लंदन विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास के भावी के प्रोफेसर श्री एच. डॉडवेल। उपर्युक्त सूची निर्णायक रूप से दिखाती है कि डब्लू. डब्ल्यू. हंटर या एच.एच. रिस्ले द्वारा किए गए दावे को कि, भारत के नाम का कोई ऐतिहासिक शोध नहीं था, वह असत्य था। (वार्षिक रिपोर्ट, इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग, ए.एफ.एम. अब्दुल अली, कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा, 21 अप्रैल, 1927, बंगाल सरकार, राजनीतिक विभाग, रिकॉर्ड्स शाखा, फा. 2 आर/2/27, पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार)। आईआरडी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन शोधकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड तक पहुंचने

के लिए कीमत के रूप में एक खोज शुल्क का भुगतान किया गया था। ("निजी पार्टियों" पर लगाए गए खोज शुल्क से 275 रुपये एकत्र किए गए थे, जबकि अधिकारियों को मुफ्त में रिकॉर्ड प्रदान किए गए थे, आईबीआईडी, पृष्ठ 3)।

कहानी का तात्पर्य यह है कि 1925 से ब्रिटिशों के पिछले दो दशकों में, गैर-आधिकारिक भारतीयों के पास ही अभिलेखों तक की पहुंच संभव थी; इसके अलावा, स्वतंत्रता तक केवल 1880 के रिकॉर्ड शोधकर्ताओं के लिए खुले थे। हमने यहां ब्रिटिश नीति पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन हमें भारतीय नागरिकों के सरकार के रिकॉर्ड तक पहुंचने के अधिकार में भारतीय राष्ट्रवादियों की भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए। विशेष रूप से एम.जी. रानडे (1842 - 1901) ने अपने राज ऑफ मराठा पावर (1900) लिखते हुए पेशवा दफ्तर रिकॉर्ड्स तक पहुंच हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन दिनों रिकॉर्ड्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी सरकार के कब्जे में थे और रानडे को वर्षों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था और आखिरकार रिकॉर्ड्स प्रतिलिपि पर सेंसरशिप के अधीन सीमित पहुंच की अनुमति दी थी। अभिलेखागार में बंद दरवाजा नीति के खिलाफ इस संघर्ष में रानडे के सहयोगी वी.के. राजवाड़े (1863 - 1926) थे। जिसे सरकार द्वारा मराठा के अभिलेखों तक पहुंच से इनकार कर दिया गया है, उन्होंने भारतीय इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की, संस्था के माध्यम से स्वयं की एक अभिलेखागार संग्रह परियोजना शुरू की। इन गतिविधियों को 'अभिलेखागार आंदोलन' के नाम से जाना जाता है, जो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित थे, जिसने, निश्चित रूप से ब्रिटिश संदेह और शत्रुता को उकसाया।

6. 1919 से भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग के नीति सलाहकार की भूमिका

इंग्लैंड (1914) में सार्वजनिक अभिलेखों पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण परिणाम 1918 में भारत सरकार से राज्य सचिव को एक प्रस्ताव था: संग्रह के संबंध में सरकार को सलाह देने, अभिलेखों के प्रकाशन इत्यादि के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए (शिक्षा विभाग, सामान्य ए, अप्रैल 1918, संख्या 1-17)। भारत सरकार द्वारा एक और प्रस्ताव यह था कि प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय रिकॉर्ड ऑफिस में जिला रिकॉर्ड एकत्र किए जा सकते हैं और पुराने प्रांतीय रिकॉर्ड केंद्रीय रिकॉर्ड ऑफिस में एकत्र किए जा सकते हैं। इसके बाद के प्रस्ताव को भारत के विदेश सचिव ने खारिज कर दिया था, जिन्होंने सोचा था कि केंद्रीय रिकॉर्ड ऑफिस में सभी पुराने रिकॉर्डों को केंद्रीकृत करना अवांछनीय था: "स्थानीय भावना [यानी प्रांतीय सिविल सेवकों की भावना] सम्भवतः हम केंद्रीकरण के इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करेंगे"। (शिक्षा विभाग, जनरल-ए, अगस्त 1919, संख्या 1 - 21)। शायद राज्य सचिव का अनुमान सही था, लेकिन प्रांतीय रिकॉर्ड कमरों में जिला अभिलेख एकत्र करने का प्रस्ताव एक अच्छा विचार था; वास्तव में यह सर जॉर्ज फोरेस्ट से आया हुआ विचार था जब उन्होंने इंग्लैंड में रॉयल कमीशन के लिए एक ज्ञापन में अपना विचार दिया और यह भारतीय कारखाने के रिकॉर्ड के विशेषज्ञ विलियम फोस्टर द्वारा भी समर्थित था। (शिक्षा विभाग,

जनरल-ए, अक्टूबर 1915, संख्या 19 - 21)। लेकिन इस सुझाव पर इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा काम नहीं किया गया था और इस प्रकार जिला रिकॉर्ड पूरी तरह से उपेक्षित रहे। हालांकि, विभिन्न प्रांतीय राजधानियों में उनके वार्षिक सत्रों में ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग ने स्थानीय रिकॉर्डों को सामने लाना शुरू कर दिया और लंबे समय तक इसने क्षेत्रीय रिकॉर्ड्स आयोगों के संगठन का नेतृत्व किया, जिसमें कुछ चुनिंदा जिला रिकॉर्ड और स्थानीय दस्तावेज प्रकाशित हुए।

ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग का उद्देश्य मूल रूप से अभिलेखागार के कार्य हेतु अधिकारियों के लिए एक बैठक का आधार बनना था, लेकिन यह विभिन्न तरीकों से उस एजेंडा से कहीं अधिक हो गया। सर जदुनाथ सरकार ने बाद में स्मरण किया कि यह कैसे विकसित हुआ: "1919 में भारत सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग के नाम पर एक छोटा परामर्श निकाय बनाया। यह केन्द्रीय कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स और तीन प्रेसीडेंसी के रिकॉर्ड अधिकारियों, साथ ही इस विभाग के बाहर से तीन ऐतिहासिक विशेषज्ञों से बना था - जिनमें से मैं अकेला उत्तरजीवी हूँ। इसका कार्य भारत सरकार को अपने आधिपत्य में रिकॉर्ड्स के संरक्षण, वर्गीकरण, लिस्टिंग और कैलेंडर पर सलाह देना था और उन्हें प्रिंट करने और पांडुलिपियों को सार्वसाधारण तक पहुंचाने हेतु सुझाव देना था। हमने जल्द ही यह पाया कि हाल ही में भारत में प्राप्त मध्ययुगीन स्थितियों के तहत, सार्वजनिक चरित्र के कई ऐतिहासिक दस्तावेज निजी कब्जे में थे और ये सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालयों में दस्तावेजों की मात्रा, पुरातनता और मूल्यों से कहीं अधिक थे। हमने यह भी महसूस किया कि सरकारी निधि इंपीरियल रिकॉर्ड्स को वांछनीय गति और दक्षता के साथ संपादित करने और प्रिंट करने की लागत प्रदान नहीं कर सकता है और इस कार्य में स्वैच्छिक गैर-आधिकारिक श्रमिकों की सहायता को शामिल करना बहुत जरूरी था। इसलिए, दूसरे वर्ष में, भारत सरकार ने सीमित और पूरी तरह से विभागीय मूल निकाय में संबंधित और सह-चयनित सदस्यों के नाम पर कई बाहरी विद्वानों को जोड़कर हमारे आयोग का विस्तार किया।" (13 दिसंबर 1937 को लाहौर में चौदहवें सत्र में, आईएचआरसी के अध्यक्ष सर जदुनाथ सरकार का भाषण)।

आईएचआरसी ने नियमों को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके तहत शोधकर्ताओं को 1925 से रिकॉर्ड तक पहुंच देना शुरू हो गया। इस निकाय का अन्य योगदान यह था कि यह भारत के विभिन्न हिस्सों से इतिहासकारों को एक साथ लाया गया और इस प्रकार भारतीय इतिहास कांग्रेस (1935) की स्थापना से कई पहले अखिल भारतीय मंच प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त आधिकारिक पुरालेखन और पेशेवर इतिहासकारों के बीच बातचीत का विकास इस परियोजना के चरण IV पर मेरी अगली रिपोर्ट का विषय होगा।

सबासाची भट्टाचार्य

टैगोर नेशनल फेलो।

अनुलग्नक संख्या II

कार्यपद्धति

1. 1911-1926 के अभिलेखागार के इतिहास के इस चरण में, मैंने पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार से काफी मात्रा में डेटा प्राप्त किया क्योंकि यह वह चरण था जब राजधानी और इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग को कलकत्ता से नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था, यह प्रक्रिया लगभग 1926 में पूरी हो गई। मुझे एनएआई, नई दिल्ली की तुलना में कलकत्ता के राज्य अभिलेखागार में रिकॉर्ड विभाग के नए स्थान पर रिकॉर्ड के स्थानांतरण पर अधिक डेटा प्राप्त हुआ।
2. मेरे द्वारा अपनायी गई डेटा संग्रह की विधि आमतौर पर अभिलेखीय शोध में होती है: फाइलों का ढेर जो मुझे प्राप्त हुआ था इसमें से मेरे शोध प्रोजेक्ट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक फाइलों की पहचान करने के लिए इंडेक्स वॉल्यूम स्कैन (मुख्य रूप से गृह विभाग, सार्वजनिक शाखा; कुछ वर्षों में शिक्षा विभाग जब आईआरडी वहां स्थानांतरित किया गया था), करने के लिए और मेरे द्वारा चुने गए रिकॉर्ड की डिजिटलीकृत या जीरोक्स की गई प्रतिलिपियों की मांग करने के लिए। मैंने प्रतिलिपि सेवा के रूप में सामान्य शुल्क चुकाया है।
3. एनएआई में मैंने जिस प्रक्रिया का पालन किया है, वह ये है कि मेरे द्वारा चुने गए रिकॉर्ड से बने डिजिटल या फोटो प्रतियां का होना, और जिस पर सचिवालय सहायता के साथ कहीं और काम करना। एनएआई शोध कक्ष ने मुझे अपने दस्तावेजी स्रोतों के संग्रह के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की हैं। हालांकि, अभिलेखागार के इतिहास का विश्लेषण और लेखन के प्रयोजनों के लिए एनएआई शोध कक्ष आदर्श नहीं है क्योंकि उस कमरे में एक दर्जन या उससे अधिक लोग बैठते हैं और वहां सचिवीय सहायता संभव नहीं है।
4. 19वीं सदी के अंत और 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रकाशित इस परियोजना के प्रयोजनों के लिए मुझे जो पुस्तकें चाहिए, वह राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में उपलब्ध हैं।

सबासाची भट्टाचार्य

**संस्कृति अनुसंधान के लिए टैगोर राष्ट्रीय फेलोशिप
(छमाही रिपोर्ट के लिए टेम्पलेट)**

1. संस्थान : राष्ट्रीय अभिलेखागार
2. टैगोर राष्ट्रीय फेलो का नाम : सबासाची भट्टाचार्य
3. फेलोशिप कार्यकाल : 4 जून 2012 से 3 जून 2014 तक
4. अवधि के लिए रिपोर्ट : जनवरी 2014 से जून 2014
5. छह-मासिक रिपोर्ट : संख्या IV
6. परियोजना शीर्षक : औपनिवेशिक अभिलेखागार नीति, 1858- 19 47 और भारत में प्रारंभिक आधुनिक इतिहास लेखन
7. अनुसंधान कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी : संलग्न टिप्पणी (अनुलग्नक I) के माध्यम से / जनवरी 2014 से जून 2014 अवधि के दौरान अनुसंधान पर रिपोर्ट, ।
8. कार्यप्रणाली : इस रिपोर्ट के अनुलग्नक -II के माध्यम से
9. कोई नहीं, क्योंकि केवल वर्तमान फेलोशिप के कार्यकाल के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों को एक साथ रखे जाने के बाद ही प्रकाशन संभव होगा और एनएआई द्वारा प्रकाशन के लिए एक पुस्तक के रूप में लिखा जाएगा।
10. उपरोक्त अनुसार; डीजी, एनएआई के निमंत्रण पर, मैंने एनएआई स्थापना समारोह, 2014 के अवसर पर इस परियोजना के स्थापना दिवस विषय पर व्याख्यान दिया; एक और सार्वजनिक व्याख्यान की विषय-वस्तु तैयार है और जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं व्याख्यान देने के लिए तैयार हूं।
11. क्षेत्र के कार्य पर टिप्पणी : ऊपर मद 8 देखें।
12. परियोजना की मुख्य विशेषताएं/प्रगति : यह रिपोर्ट संख्या IV शुरू की गयी परियोजना को पूरा करती है

13. कठिनाइयों, यदि कोई हो : एनएआई में कार्य परिस्थितियां अति उत्कृष्ट हैं।
14. अन्य अकादमिक कार्य : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने मई 2014 में 1920-1947 की अवधि में मेरे द्वारा लिखित ऐतिहासिक कार्य को प्रकाशित किया है।

फेलो/स्कॉलर का हस्ताक्षर और तिथि: 30 जून, 2014

संस्थान के प्रमुख की टिप्पणियां:

हस्ताक्षर और तारीख:

अनुलग्नक ।

परियोजना कार्य, जनवरी 2014 से जून 2014 पर रिपोर्ट नंबर IV

परियोजना शीर्षक: औपनिवेशिक संग्रहण नीति, 1858 - 1947

द्वारा

सबासाची भट्टाचार्य,

टैगोर नेशनल फेलो

1926-1947 की अवधि में वर्तमान रिपोर्ट संख्या IV, पहले लिखी गयी तीन रिपोर्टों की पूर्ववर्तिता में थी। चूंकि यह इस परियोजना की आखिरी रिपोर्ट है, मोनोग्राफ के रूप में अपने निष्कर्षों के प्रकाशन से पहले, शुरुआती रिपोर्टों की समीक्षा करना और प्रमुख बिंदुओं को दोहराना उपयोगी होगा।

पृष्ठ - भूमि

चरण 1858 से 1872 पर रिपोर्ट । मैं निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया था

(क) ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति होने पर, , रिकॉर्ड सिस्टम को पुनर्गठित करने के लिए भारतीय सरकार के प्रयास और 1858 में इसके अंत से 1872 में इसके विघटन तक रिकॉर्ड कमेटी पर विचार-विमर्श। (ख) यह ध्यान दिया गया था कि सरकार केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय, या 'मुनीमेंट रूम' के निर्माण पर धन और कार्यबल के अभाव में फैसला करने में असमर्थ थी। (ग) हमने इतिहासकारों या अभिलेखागारों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर भी ध्यान दिया, जिन्होंने रिकॉर्ड का संयोजन और प्रकाशन करने में योगदान दिया, उदाहरण रेव. जेम्स लांग, जे. टल्बॉयज़ व्हीलर, डब्ल्यू. सैटन-कर्, और सर विलियम हंटर। दूसरे चरण 1872 से 1891 में, रिपोर्ट संख्या II के विषय में, हमने दो नीतिगत रुझानों की ओर इशारा किया: (क) कई वर्षों तक केंद्रीय इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग बनाने के सवालों पर दुविधा के बाद, अंततः 1891 में सरकार द्वारा इस विचार को स्वीकार किया गया था, (ख) और गैर-अधिकारियों को अभिलेखों तक पहुंचने की इजाजत देने के लिए नौकरशाहों के कड़े विरोध के बावजूद यह निर्णय लिया गया था। रिपोर्ट III में हमने चरण 1891 से 1911 में तीन रुझानों की पहचान की: (क) इंग्लैंड में मास्टर ऑफ रोल्स द्वारा अनुशंसित अंग्रेजी मॉडल, और कीपर ऑफ इंग्लिश रिकॉर्ड ऑफिस को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन यह इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग (सहायक सचिव के पद के बराबर) के प्रमुख को दिए गए निम्न पद, साथ ही अभिलेखागार को विकसित करने में वित्तीय बाधाओं के कारण अलभ्य आदर्शस्वरूप बना रहा। (ख) सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच से गैर-अधिकारियों, यानी शोधकर्ताओं और आम जनता को दूर रखने की नीति जारी रही। 1911 से कलकत्ता से नई दिल्ली तक राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा के साथ एक नया चरण शुरू हुआ, और इस प्रकार कलकत्ता से इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग का स्थानांतरण हुआ। मैंने 1911 - 1926 में इस चरण में मुख्य विकास को रेखांकित किया है: (क) क्विन्स

वे, अब जनपथ, पर नई इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग की इमारत का आर्किटेक्ट, सर एडविन लुटियंस था। 1926 में इमारत पूरी हो गई और इसमें कार्य करना शुरू हुआ। (ख) 1914 में इंग्लैंड में सार्वजनिक अभिलेखों पर रॉयल कमीशन की सिफारिशों के साथ-साथ भारत के राज्य सचिवों के परामर्श ने भारतीय नौकरशाही में जागरूकता पैदा की कि रिकॉर्ड विभाग महत्वपूर्ण था। (ग) 1919 में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग का गठन हुआ, उपरोक्त उल्लिखित आयोग द्वारा दीए गए सुझाव ने, रिकॉर्ड विभाग के अधिकारियों और अकादमिक इतिहासकारों के बीच आंतर-क्रिया के लिए एक मंच बनाया, जिन्होंने अभिलेखागार के लिए खुली व्यापक पहुंच के लिए दबाव डाला।

निम्नलिखित पृष्ठों में हम 1926 से अभिलेखीय नीति के क्रमिक विकास के अंतिम चरण में प्रमुख मुद्दों और विकास को संबोधित करते हैं, जब इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग ने 1947 यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति से दिल्ली में काम करना शुरू किया, और रिकॉर्ड विभाग को 'राष्ट्रीय अभिलेखागार' के रूप में पुनः पदनामित किया गया। इस चरण 1926-47, के विवरण में प्रवेश करने से पहले, आइए हम अपने पहले की रिपोर्ट में उभरे प्रमुख नीतिगत रुझानों को सार रूप में प्रस्तुत करते हैं और इसे फिर से एक बार दोहराते हैं।

अभिलेखागार: इंपीरियल शासन में एक प्रणालीगत आवश्यकता

1858 से भारत सरकार की अभिलेखीय नीति में बुनियादी उद्देश्य क्या थे? वर्तमान परियोजना पर शोध से पता चलता है कि इंपीरियल सरकार के लिए अभिलेखागार एक प्रणालीगत आवश्यकता थी। इसके पिछे निम्नप्रकार के कारण थे। सबसे पहले, अभिलेखागार पूर्व निर्णय के स्मरण के रूप में कार्य करते थे। समझौता और पूर्व निर्णय पर स्थापित कार्रवाई पर ध्यान देने की ब्रिटिश आदत को देखते हुए और यह भी तथ्य कि कानून की अदालतों में मामले जो उनके सामने आये थे के व्याख्यात्मक पूर्व निर्णय के माध्यम से कानून बनाये थे, ब्रिटिश भारतीय प्रशासकों के लिए अपेक्षित कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली प्रक्रिया में प्रशासनिक कार्रवाई के पूर्व निर्णय पर ध्यान आकर्षित करना बहुत महत्वपूर्ण था।

दूसरा, इंपीरियल रिकॉर्ड क्षेत्रीय दावों और ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अधिकारों और बाद में अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत सरकार के दावों की स्थापना के साधनों के रूप में भी कार्य करता था। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था, अंग्रेजों ने भारतीय संपत्तियों को तलवार से ले लिया था और वे उसी तलवार के उचित उपयोग से इसे अपने पास रख सकते थे। लेकिन ब्रिटिश भारतीय सरकार भी एक कानूनी तर्क के माध्यम से अवपीड़न को न्यायसंगत साबित करने के लिए चिंतित थी। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि रिकॉर्ड के पहले सेट को वर्गीकृत और संग्रहीत किए जाने वाले विदेश विभाग के रिकॉर्ड थे। 1889 में प्रोफेसर जी.डब्ल्यू. फोरेस्ट को सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया था। (होम (पब्लिक) मार्च 1891, संख्या 24-42, एनएआई, पुनः जी. फोरेस्ट

की नियुक्ति)। विदेशी विभाग के रिकॉर्ड के प्रमुख महत्व की तरह ही इसे प्रभाव बनाया जाएगा, यदि आप एचिसन के रियासतों जिसे पहले 'देश शक्तियां', 'मूल राज्य' आदि कहा जाता है साथ ही साथ पड़ोसी विदेशी शक्तियों के साथ संधियों और अनुबंध के संग्रह पर नज़र डालते हैं। (सी.यू. एचिसन, एड., ए कलेक्शन ऑफ ट्रीटिज, एंगेजमेंट्स एंड सनड्स, कलकत्ता गवर्नमेंट प्रेस, 1892-93, वॉल्यूम I-XI)। यहां तक कि आजादी के बाद भी भारत सरकार ने रियासतों, या मैकमोहन लाइन, या हिमालय के या उससे बाहर के राज्यों के साथ भारत के संबंधों के एकीकरण से निपटने में इन संग्रहित डेटा का उपयोग किया।

तीसरा, ब्रिटिश भारतीय सरकार ने न केवल बाहरी संबंधों के प्रयोजनों के लिए, बल्कि आंतरिक नीति बनाने के लिए भी दस्तावेजों के संरक्षण की सराहना की। उदाहरण के लिए, उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत जनजातीय समूहों से कैसे निपटें (जो राज्य के लिए संभालना मुश्किल थे जैसे आज पाकिस्तान के लिए हैं), या कौन से जातीय समूह सेना के लिए सिपाही के रूप में भर्ती करते हैं (यह अधिकारियों की गड़बड़ी और पुराने रिकॉर्ड में विकसित नस्लीय रूढ़िवादों पर निर्भर करता था) या भूमि राजस्व कितना एकत्र किया जाना था (यह 30 या अधिक साल पहले किए गए भूमि राजस्व निपटान संचालन पर आधारित था)। उस तरह के सभी नीतिगत विचारों पर ध्यान आकर्षित किया गया कि ब्रिटिशों ने पहले के समय में क्या सीखा था। यहाँ ऐतिहासिक बयानों में एक सामान्य त्रुटि पर सवाल उठाया जाना चाहिए। कई इतिहासकार समय-समय पर नीति घोषणाओं के संदर्भ में नीति को परिभाषित करते हैं; असल में नीति वह प्रवृत्ति है जो सरकार द्वारा छोटी कार्रवाइयों की श्रृंखला में विकसित होती है, जो नीति के रूप में जरूरी नहीं है। (सबासाची भट्टाचार्य ब्रिटिश राज की वित्तीय नींव, नई दिल्ली, 2005, 'प्रस्तावना' में मेरा यह तर्क था। जब ब्रिटिश भारतीय सिविल सर्वन्ट ने पहले के रिकॉर्ड में देखा तो उन्हें शायद ही कभी उस तरह की घोषणाएं मिलीं, लेकिन उन्होंने उन कार्रवाइयों को देखा जो सामूहिक रूप से इस सोच दिशा का निर्माण करते थे जो नीति थी।

अंत में, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने इतिहास में अपने स्थान का दावा करने के साधन के रूप में उनके लिए एक स्मारक के रूप में एक अभिलेखागार बनाया है। यह फिर से घोषित नीति नहीं थी, लेकिन स्पष्ट रूप से पृथक और अनियंत्रित कार्रवाइयों की एक श्रृंखला का नतीजा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यावहारिक कारण, जैसे कि मैंने पहले उल्लेख किया है, प्रबल था। ऐसा लगता है कि 1861 में सिविल ऑडिटर, सैंडमैन ने पहले 'ग्रांड सेंट्रल आर्काइव' का सुझाव दिया था और इसका कारण यह था कि बहुत से पुराने रिकॉर्ड विभागीय रिकॉर्ड रूम के अलमारियों का बोझ बढ़ाते थे। (सैंडमैन का जापन, गृह (सार्वजनिक), दिसंबर 1872, संख्या 647, एनएआई)। 1862 में कलकत्ता में एक समिति ने "पूरी तरह से ऐतिहासिक और सांख्यिकीय हित" के पुराने रिकॉर्ड से "व्यावहारिक कार्यालयीन उपयोगिता" के रिकॉर्ड को अलग करने की सिफारिश की। लेकिन कलकत्ता समिति का काम शून्य हो गया, क्योंकि यह अक्सर आर्थिक तंगी के कारणों से हुआ। इसके अलावा, इस समय भारत सरकार के उच्चतम निवासी अधिकारियों में प्रचलित विचार यह था कि भारत सरकार के चुनिंदा

अभिलेखों का प्रकाशन इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग की स्थापना से अधिक उपयोगी था; वह वाइसराय नॉर्थब्रुक का विचार था। (भारत सरकार से भारत के राज्य सचिव को, संख्या 95, 13 दिसंबर 1872, एनएआई)। 1889 में जी. डब्ल्यू. फोरेस्ट को विदेशी विभाग के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए अधिकृत किया गया था। 1891 में जब सरकार ने आखिरकार इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग स्थापित करने का फैसला किया, तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य विदेशी विभाग के रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना था। 1897 में कुछ और वर्षों के बाद भारत के विदेश सचिव ने भारत सरकार को दस्तावेजों की प्रेस-सूचियां तैयार करने का निर्देश दिया, जिससे विभिन्न विभागों और अधीनस्थ सरकारों के रिकॉर्ड सुलभ हो गए। (अधीनस्थ सरकारें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में रिकॉर्ड रूम के साथ प्रांतीय सरकारें थीं)। इस प्रकार प्रेस-सूचियां और दस्तावेजों के कैलेंडर के साथ इंपीरियल रिकॉर्ड रूम इस परिभाषा के स्वीकृत भाव की तरह अभिलेखागार के रूप में दिखाई देने लगा है। 1860, 1862, 1889, 1891, 1897 की इन असंगत प्रशासनिक घटनाओं ने इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफिस का निर्माण किया है। ऐतिहासिक भावना यहां कार्य कर रही थी। और यह संभव है कि सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1838 में इंग्लैंड की संसद में पारित हो गया (रोल ऑफ मास्टर की अभिरक्षा में रिकॉर्ड रखे) जो इस विचार दृष्टी से असंगत नहीं था।

कुल मिलाकर, अपने स्वयं के व्यावहारिक कारणों के लिए, औपनिवेशिक राज्य ने अभिलेखागार को अस्तित्व में लाया। ऐतिहासिकता की भावना ने भी एक भूमिका निभाई। ब्रिटिश भारत के अपने प्रसिद्ध इतिहास में जेम्स मिल के दावे को कोई भी याद कर सकता है, कि भारतीय सभ्यता में ऐतिहासिकता की भावना नहीं थी और इतिहास का कोई काम नहीं हुआ। (जेम्स मिल, ब्रिटिश भारत का इतिहास, (लंदन, 1844, पुनर्मुद्रण, दिल्ली 1972) खंड I, पीपी 370-373।)। अंग्रेजों ने अपनी ऐतिहासिक चेतना पर गर्व महसूस किया और अभिलेखागार उनके ऐतिहासिक स्मारक होंगे।

अभिलेखों तक पहुंच: अभिलेखागार खोलने के खिलाफ औपनिवेशिक नौकरशाही

अभिलेखागार की अवधारणा का तात्पर्य है कि यह देश की स्मृति का संरक्षक है। इस परियोजना में उल्लिखित अभिलेखागार नीति से पता चलता है कि औपनिवेशिक भारत में यह मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन का अवउत्पाद था। इस तथ्य का स्मरण रहे कि शब्द अभिलेखागार पहली बार फ्रांस की मुद्रा पर आया था, जबकि इसके लिए ब्रिटिश शब्द रिकॉर्ड रूम था। यह स्मरण रहे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना और अभिलेखागार के अभिलेखों तक पहुंच के सार्वजनिक अधिकार के संस्थागतकरण की साक्षी रही है। (मिशेल डुचेन अभिलेखागार से जानकारी प्राप्त, उपयोग और हस्तांतरण करने के लिए बाधाएं (यूनेस्को, पेरिस, 1983) और अमेरिकी आर्किविस्ट में 'यूरोपीय अभिलेखागार का इतिहास और यूरोप में अभिलेखीय पेशे का विभाग' वॉल्यूम 55, विन्टर 1992; कैथरीन एल. कॉक्स, 'विचारधारा, व्यावहारिकता और वित्तीय आवश्यकता: राष्ट्रीय अभिलेखागार का निर्माण

1789-1801', फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, पीएचडी शोध प्रबंध, 2007)। यह भी स्मरण रहे कि 1938 के उत्तरार्ध में इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग ने उन सभी शोधकर्ताओं तक पहुंच की इजाजत नहीं दी जो रिकॉर्ड देखना चाहते थे। 1939 में जब प्रतिबंध हटा लिया गया तो सार्वजनिक पहुंच की सीमा यह थी कि 1880 से पहले के रिकॉर्ड शोधकर्ताओं द्वारा देखे जा सकते थे। इस प्रकार, हालांकि 1919 से भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग (सर जदु नाथ सरकार समेत) ने शोधकर्ताओं को स्वीकार करने और उनकी मदद करने के लिए कुछ संकेत दिए, खुली पहुंच केवल 1939 में आई थी और यह साठ साल से अधिक पुराने दस्तावेजों तक ही सीमित थी। इस तथ्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि अभिलेखागार भारत के ब्रिटिश शासन के केवल पिछले आठ वर्षों में पहुंच के लिए खुला था। कई अन्य देशों में राष्ट्रीय अभिलेखागार जनता के लिए खुले थे, लेकिन औपनिवेशिक भारत में नहीं।

इस बात के बहुत सारे प्रमाण हैं कि औपनिवेशिक नौकरशाही इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग को उस शीर्षक के सुझाव के अलावा अन्य किसी भी रूप में इसे मानने के इच्छुक नहीं थे। शोधकर्ताओं या भारतीय जनता को अभिलेखागार खोलने के लिए भारत में सिविल सर्वन्ट के विरोध को दर्शाने वाले प्रकरण का अध्ययन ए.आर. कुलकर्णी और अन्य ने किया है। (ए आर कुलकर्णी, संपादित., हिस्ट्री इन प्रैक्टिस: हिस्टोरीअन एंड सोर्सस ऑफ मीडिईवल डेक्कन-मराठा, दिल्ली, 1993)। 1897 में दक्कन वर्नाक्युलर सोसाइटी ने सरकारी अभिरक्षा में पेशवा दफ्तर में दस्तावेजों के उद्धरण को प्रिंट करने की अनुमति के लिए बॉम्बे सरकार से अनुरोध किया था। बहुत विलंब के बाद अनुमति दी गई थी बशर्ते कि, सरकार ने कहा, एम जी रानडे द्वारा प्रस्तावनारूपी निबंध प्रकाशन से हटा दिया गया। 1904 में इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग के अध्यक्ष सी. आर. विल्सन ने लिखा: "भारत सरकार के रिकॉर्ड का अध्ययन करने के लिए वर्तमान में जनता को क्या सुविधाएं हैं। व्यावहारिक रूप से कोई नहीं"। (सी. आर. विल्सन ज्ञापन, 29.3.1904, गृह (सार्वजनिक) सितंबर 1904, संख्या 98, एनएआई)। 1910 में जब राज्य सचिव ने दस्तावेजों के कैलेंडर को तैयार करने का सुझाव दिया तो रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुंच का सवाल फिर से सामने आया। भारत सरकार के विदेश विभाग के एच. जी. स्टोक्स ने "राजनीतिक रूप से या अन्यथा सरकार के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री प्रदान करने की मूर्खता" की ओर इशारा किया। (एच. जी. स्टोक्स 'टिप्पणी 24.2.1910, (सार्वजनिक) ए प्रोग्राम्स., अप्रैल 1919, संख्या 1-5, राष्ट्रीय अभिलेखागार)। शिक्षा विभाग के ए. एफ. शॉल्फिल्ड ने "उन प्रोत्साहनों और अवसरों के बारे में इंगित किया जो रिकॉर्ड खोलने के कारण निराशाजनक और अयोग्य लेखकों, बेईमान पत्रकारों और इनके जैसों के लिए प्रदान किए जाते हैं", और इसके परिणाम "सरकार के लिए विनाशकारी" होंगे। (ए. एफ. शॉल्फिल्ड द्वारा टिप्पणी, शिक्षा विभाग, 28.4.1914, जनरल, ए प्रोग्राम्स, जून 1914, एनएआई)। उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच के अंतर पर भी ध्यान दिया: "भारत में शिक्षा का कोई अभिजात वर्ग नहीं है, इतिहास का कोई स्कूल, ऐतिहासिक शोध, प्रमाण का वैज्ञानिक उपयोग, आदि नहीं है।

असल में इससे पहले, जब कैलेंडर और प्रेस-सूचियों को तैयार करने का विचार चर्चा में था, आईसीएस से इसके लिए विरोध हुआ था। एच. एच. रिस्ले ने "प्रेस सूचियों के मार्गदर्शन से लोगों को हमारे रिकॉर्ड में छानबिन करने के लिए छूट देने" हेतु अपने विरोध के बारे में लिखा था क्योंकि इस तरह की सामग्रियों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से उपयोग किया जाने का खतरा था। " (एच. एच. रिस्ले की टिप्पणी 23 जून 1904, होम, पब्लिक, ए प्रोग्राम्स, सितंबर 1904, संख्या 98, एनएआई)। ऑक्सफोर्ड में सेंट एंटनी कॉलेज में मेरे पूर्व सहयोगी, जोहान्स एच. वोइग्ट ने इस मत प्रवृत्ति का सर्वेक्षण किया है। उनका तर्क है कि 1920 के दशक में राजनीतिक कारणों से अभिलेखागार खोलने के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। जबकि पहले ब्रिटिश भारत में सिविल सेवकों ने अभिलेखागार खोलने का विरोध किया था, 1920 के दशक में इस नए दृष्टिकोण ने यह तर्क दिया था कि रिकॉर्ड से वास्तविक इतिहास का ज्ञान भारतीय शिक्षित मध्यम वर्गों के बीच ब्रिटिश विरोधी भावनाओं की लहर को रोकने के लिए अच्छा होगा। वोइग्ट के अनुसार यह ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध प्रोफेसर रामसे मुड़र थे, जिन्होंने लगभग सरकार को राजी किया था। मुड़र का मानना था कि "शिक्षित भारत को पूर्ण राजनीतिक विवेक प्राप्त करने के लिए" ऐतिहासिक जांच और आलोचना की भावना "की आवश्यकता थी।" (जे.एच. वोइग्ट, 'भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान और लेखन के लिए ब्रिटिश नीति, 1870 - 1930,' भारतीय आर्थिक और सामाजिक इतिहास समीक्षा, खंड III, 1966, पीपी 137-149; 7 दिसंबर, 1917 को ई.डी. मैकलगन को मुड़र के पत्र का हवाला देते हुए, एडू. प्रोग्राम्स, अप्रैल 1918, संख्या 1-17)।

यह सवाल उठता है कि क्या मुड़र, केवल अकादमिक लेखक, सिविल सेवकों की लॉबी को प्रभावित करते हैं। उनके लिखने के 20 साल बाद भी इंपीरियल रिकॉर्ड रूम शोधकर्ताओं के लिए बंद रहा। अभिलेखीय रिकॉर्ड खोलने के लिए कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक इतिहासकार विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, प्रमुख सार्वजनिक प्रवक्ता के. टी. तेलंग और राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी एम. जी. रानडे ने शुरू किया 'अभिलेखागार आंदोलन' था। (ए.आर. कुल्कर्णी के निबंधों का संग्रह प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री में, और प्राची देशपांडे ने 2007 में प्रकाशित उनकी थीसिस में इस आंदोलन पर ध्यान आकर्षित करती हैं; प्राची देशपांडे, क्रिएटिव पास्ट्स: हिस्टोरिकल मेमरी एंड आईडेंटिटी इन वेस्टर्न इंडिया, 1700-1960, दिल्ली, 2007)। यह पेशवा दाफ्तर अभिलेखों के शोधकर्ताओं हेतु इसे खोलने के लिए बॉम्बे प्रेसीडेंसी सरकार को मनाने का प्रयास था; इस दबाव ने तुरंत परिणाम नहीं दिया लेकिन इसके लाभकारी परिणाम राजवाड़े जैसे मराठा इतिहासकारों द्वारा निजी रिकॉर्ड का अनौपचारिक संग्रह था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग ने सरकार को अभिलेखागार के नियमों को उदार बनाने के लिए दबाव डाला और 1939 में शोधकर्ताओं के सार्वजनिक अभिलेखों तक पहुंच को अंतिम रूप दिया गया। क्या यह एक और संकेत था कि अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ खो दी थी? या उनके जाग उठने का अर्थ था कि रिकॉर्ड में इतिहास को हमेशा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता है? गौरतलब है कि अभिलेखागार की यह मुक्ति इंपीरियल शासन के आखिरी दिनों में हुई। यह हेगेल के कहावत की याद दिलाता है कि मिनर्वा का उल्लू संध्याकाल में उड़ता है।

चरण 1926 - 1947 में प्रमुख विकास

1926-47 के वर्षों में निम्नलिखित प्रमुख विकास हुए। सबसे पहले, यह चरण कलकत्ता से नई दिल्ली के अभिलेखागार के स्थानांतरण से शुरू होता है। दूसरा, इस चरण में भारत सरकार की विभागीय संरचना का व्यापक पुनर्गठन और अभिलेखागार में रिकॉर्ड का परिणामी पुनर्गठन हुआ; यह सरकार की गतिविधियों के विस्तार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम और द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा किए गए परिवर्तनों को दर्शाता है। तीसरा, इन वर्षों में यह भी देखा गया कि नए भारतीय ऐतिहासिक आयोग ने अभिलेखीय नीति को आकार देने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में, हम दीर्घकालिक प्रवृत्ति, इतिहासलेखन पर संग्रहीत अभिलेखों की उपलब्धता का प्रभाव, यानी इतिहास लेखन और पद्धति के विकास को देखते हैं।

1926 से इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग का नई दिल्ली में स्थानांतरण

कलकत्ता में पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार में वर्ष 1927 की एक फाइल है, जो यथार्थ तिथि को अभिलेखित करती है जब ब्रिटिश भारत, की पूर्व राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली में रिकॉर्ड के आंशिक स्थानांतरण के बाद वर्तमान एनएआई भवन का उद्घाटन किया गया। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख, जिसे भारत सरकार के कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में नामित किया गया, ने कलकत्ता से लिखा था: "नई दिल्ली में इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफिस की इमारत वर्ष (1926) के दौरान पूरी की गई थी ... 1899 के बाद से क्राउन रिकॉर्ड्स को दो सहायक, 4 क्लर्क, 6 सॉर्टर्स और दफ्तरिज, 3 चपरासी और 4 इस्टिंग बेअर्स वाले कर्मचारियों के साथ नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। नई दिल्ली में रिकॉर्ड ऑफिस [वर्तमान में एनएआई इमारत जनपथ पर, जिसे क्वीन्स वे के नाम से जाना जाता है] 1 नवंबर, 1926 को खोला गया था। "(पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार, राजनीतिक विभाग, रिकॉर्ड शाखा, फा. सं. 2 आर 2/27, ए.एफ.एम. अब्दुल अली, सचिव, शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग, 21 अप्रैल 1927)। यह पत्र, जो हमें उन छोटे कर्मचारियों का विचार भी देता है जो रिकॉर्ड के स्थानांतरित विभाग में कार्य करते हैं, जो कम से कम 12 साल के स्थानांतरण की लंबी प्रक्रिया की शुरुआत को चिह्नित करते हैं। विभाग के प्रमुख, कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स कलकत्ता में बने रहे और धीरे-धीरे रिकॉर्ड्स को किशतों में स्थानांतरित कर दिया गया जब तक कि मार्च 1937 में सबसे पुराने, "प्री-म्यूटनी रिकॉर्ड्स" के स्थानांतरण का कार्य पूरा नहीं हो गया।

यह आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बिल्डिंग, जो वर्तमान एनएआई भवन का पुराना विंग है, मूल रूप से आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस द्वारा विचार की जाने वाली इमारत का केवल एक चौथाई हिस्सा है। उन्होंने एक हॉलो स्केअर की योजना बनाई थी जिसमें से केवल एक तरफ, सड़क का सामना करने वाला अग्रभाग वास्तव में बनाया गया था; वित्तीय कारणों के साथ-साथ निर्माण में भारी देरी के कारण पहले योजनाबद्ध अन्य तीन पक्षों को छोड़ दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध,

लुटियंस की लगातार अनुपस्थिति, और धन संबंधी कारकों में देरी होने से; शुरुआत से लेकर निर्माण कार्य पूरा होने तक 1912 से 1926 तक 15 साल लगे।

केवल कलकत्ता से स्थानांतरित रिकॉर्ड के लिए यह इमारत पर्याप्त थी; 20 साल बाद जगह अपर्याप्त हो गयी जब दस्तावेजों की मात्रा में अचानक वृद्धि हुई, क्योंकि लगभग 1 मिलियन फाइलें 1947 में शिमला से नई दिल्ली में स्थानांतरित की गई थीं। 1950 के दशक के अंत तक, विभाग के निदेशक की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली में संग्रह 5.1 मिलियन फाइलों और रिकॉर्ड के 103 हजार बाउंड वॉल्यूम से अधिक हो गया, पुस्तकालय में मुद्रित सरकारी प्रकाशनों की तो गणना ही नहीं।

भारत सरकार के विभागों और रिकॉर्ड्स का पुनर्गठन, 1923-1947

1923 और 1947 के दरम्यान विभागों के बीच कार्यों के परिवर्तित विभाजन के परिणामस्वरूप इंपीरियल सचिवालय में हुए परिवर्तनों को दर्शाते हुए रिकॉर्ड कई बार पुनर्गठित किए गए थे। पुनः वर्गीकरण और पुनर्गठन घटित होने के तीन कारक थे। पहला, भारत सरकार के कार्यों का विस्तार और विविधीकरण। दूसरा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रभाव से भारत सरकार और कुछ स्वायत्तता की कार्यवाही के साथ निर्वाचित मंत्रालयों के तहत प्रांतीय सरकारों के बीच कार्यों का विभाजन और परिणामी रिकॉर्ड रखने का विभाजन हुआ। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने विभागों को अब तक निरर्थक महत्व दिया।

1920 के दशक से रिकॉर्ड के पुनर्गठन में पहला कारक प्रमाण है। 1923 में उद्योग और श्रम के बढ़ते महत्व ने उद्योग और श्रम के नए विभाग के निर्माण को स्वीकृत प्रदान की थी। (यह आंशिक रूप से इंचास्केप कमीशन द्वारा अनुशंसित प्रशासनिक पुनर्गठन का परिणाम था)। 1923 में यह अन्य पुराने विभागों जैसे गृह, वित्त, विधान आदि के साथ कुल मिलाकर 9 विभागों का एक समूह बना; 1947 तक विभागों ने विभाजन और नए निर्माण के परिणामस्वरूप 18 की संख्या दर्ज की। महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित थे। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के निर्माण के बाद 1941 में सूचना और प्रसारण विभाग का निर्माण (जिसे पहले भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कहा जाता था, और अभी भी कुछ समय पहले तक यह भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नामक एक निजी कंपनी थी; यह 'राष्ट्रीयकरण' के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक था)। कार्य की मात्रा में वृद्धि के कारण, उद्योग और श्रम विभाग, को 1937 में दो अलग-अलग विभागों में विभाजित किया गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग बेहद बहुप्रयोजनिय था, जिसे तीन अलग-अलग शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग (1945) में बांटा गया था। 1936 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों से सैन्य विभाग के रूप में पहचाने जाने वाले सबसे पुराने विभागों में से एक का नाम बदलकर रक्षा विभाग रखा गया। जेनरेट किए गए कागजात के अभिलेखीय संगठन में परिणामी परिवर्तन के कारण इन और अन्य प्रशासनिक परिवर्तनों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

ऊपर वर्णित दूसरा कारक, भारत सरकार अधिनियम 1935 के परिणाम निम्नलिखित प्रकार से प्रमाण में था। विदेशी और राजनीतिक विभाग में दो कार्यों का संयोजन होता था - रियासत (या मूल) भारतीय राज्यों के साथ-साथ ब्रिटिश भारतीय सीमाओं, लीग ऑफ नेशंस इत्यादि से परे अन्य राज्यों के साथ संबंधों का आचरण। 1935 में बाद के कार्यों को अलग कर दिया गया और विदेश मामलों के नए विभाग को सौंपा गया, जबकि राजनीतिक विभाग को रियासतों के साथ संबंधों सहित शेष कार्यों को दिया गया था। बाद के कार्य, क्राउन प्रतिनिधि को संभालने के लिए एक नया सांविधिक प्राधिकरण बनाया गया था। गवर्नर जनरल या वाइसराय क्राउन प्रतिनिधि बन गए। अभिलेखागार में आज कश्मीर या हैदराबाद से लेकर सबसे छोटी राज्यों के रियासतों के संबंध में सभी कागजात क्राउन प्रतिनिधि रिकॉर्ड के नाम से जाने जानी वाली पूरी तरह से अलग श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसके अलावा, 1935 के बाद केन्द सरकार के कई विभागों ने प्रांतीय सरकारों को भारत सरकार अधिनियम द्वारा हस्तांतरित विषयों से संबंधित रिकॉर्ड जेनरेट करना बंद कर दिया।

तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध ने कई तरीकों से रिकॉर्ड के प्रशासन और परिणामस्वरूप संगठन को प्रभावित किया। युद्ध प्रचार करने, आकाशवाणी द्वारा प्रसारण करने और समाचार के प्रकाशन को नियंत्रित करने के लिए सूचना और प्रसारण के नए विभाग (1941) ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध की अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए कुछ नए और कभी-कभी अस्थायी विभाग बनाए गए थे, उदा. युद्ध विभाग (रक्षा विभाग से अलग), युद्ध परिवहन विभाग, कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए खाद्य विभाग, सिविल आपूर्ति विभाग, आदि. इन नए विभागों में से सबसे महत्वपूर्ण शायद युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण का कार्य करने के लिए योजना और विकास विभाग था; यह 1947 के बाद के योजना आयोग के पूर्ववर्ती था।

इसका समग्र परिणाम यह था कि स्वतंत्रता के समय 18 विभाग थे, जबकि 1923 में केवल 9 विभाग थे, और 1843 में केवल 4 विभाग थे। इस प्रकार विभागों और रिकॉर्ड्स की संख्या बढ़ती गई, जेनरेट किए गए रिकॉर्ड का विस्तृत पुनर्गठन और अनुक्रमण करना अपेक्षित है।

भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग की भूमिका

1914 में इंग्लैंड के सार्वजनिक रिकॉर्ड्स आयोग ने सुझाव दिया कि, अन्य बातों के साथ, भारत में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अन्य पूर्वाग्रह ने उन पर की जाने वाली कार्रवाई रोक दी। आखिरकार 1919 में भारत सरकार द्वारा अपेक्षित आयोग का गठन किया गया। यह रिकॉर्ड्स को संभालने वाले निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए मीटिंग ग्राउंड के रूप में शुरू हुआ। सर जदुनाथ सरकार अपने प्रारंभिक दिनों से इसके साथ जुड़े थे और उन्होंने बाद में स्मरण किया कि "यह आयोग भारत सरकार द्वारा गठित, आधिकारिक रिकॉर्ड कीपर और ऐतिहासिक विशेषज्ञों के बहुत छोटे निकाय के रूप में निर्माण हुआ ताकि उनके रिकॉर्ड का सर्वोत्तम प्रबंधन

करने, उनका संरक्षण करने, नष्ट करने, सूचीबद्ध करने, और संपादित करने के लिए देखभाल की उचित विधि प्रदान करने और सरकारी रिकॉर्ड ऑफिस के कार्य के संबंध में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर निर्णय लेने हेतु इसे और स्थानीय सरकारों को सलाह दी जा सके। "(भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग की कार्यवाही, लाहौर, 1937, सर जे. एन. सरकार द्वारा दिया गया भाषण, पृष्ठ 8)। जल्द ही यह महसूस किया गया कि कुछ पेशेवर इतिहासकारों को विश्वविद्यालयों से उनकी विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने के लिए सहयोग करना उपयोगी होगा; आगे यह भी महसूस किया गया कि, जैसा कि सरकार ने बताया, "ब्रिटिश काल के सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी सरकार के हाथों में नहीं हैं ... कई निजी व्यक्तियों, विशेष रूप से ऐतिहासिक परिवारों के प्रतिनिधियों के पास प्रथम-दर्जे के महत्व के दस्तावेज हैं।" इसलिए, 1920 में रिकॉर्ड्स आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सदस्यों के साथ-साथ सह-चयनित सदस्यों की संख्या में न केवल अधिकारियों और पेशेवर अभिलेखागारों बल्कि ऐतिहासिक अनुसंधान में रुचि रखने वाले विश्वविद्यालयों में से अकादमिक व्यक्तियों को शामिल करके इसका काफी विस्तार किया गया था। आयोग ने सरकारी अभिलेखागार और अधिकारियों को शामिल करना जारी रखा, लेकिन वे विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षाविदों से अधिक संख्या में थे। उदाहरण के लिए दिसंबर 1930 में पटना में आयोग के तेरहवें सत्र में निम्नलिखित सदस्य थे: एच.जी. रावलिनसन और एच.एल.ओ. गेर्रेट्ट, दोनों भारतीय शिक्षा सेवा (उस समय मुख्य रूप से ब्रिटिश मूल के व्यक्तियों को भारतीय शिक्षा सेवा, आईसीएस से संबद्ध एक सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था)। सर जदुनाथ सरकार, एस कृष्णास्वामी अय्यंगार और सुरेंद्रनाथ सेन ने अकादमिक प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व किया और ए.एफ.एम अब्दुल अली भारत सरकार के कीपर ऑफ रिकॉर्ड आयोग के सदस्य थे। सह-चयनित सदस्यों में विश्वविद्यालयों के कई प्रतिष्ठित इतिहासकार शामिल थे: के.पी. जयस्वाल (पटना), के. ए. निलाकांत शास्त्री (मद्रास), एस. खुदा बुख्श (कलकत्ता विश्वविद्यालय), आर.सी. मजूमदार (ढाका विश्वविद्यालय), सुबिमल चन्द्र सरकार (पटना), सुशोभान चंद्र सरकार (ढाका विश्वविद्यालय), राधा कुमुद मुखर्जी (लखनऊ), ए.बी.ए.हालेम (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), डी.वी.पोतदार (पुना), एस.के.भुयान (गुवाहाटी), टी.जी.पी. स्पिअर (दिल्ली), स्टेला क्रैमिस्च (कलकत्ता विश्वविद्यालय), आदि सभी (भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग की कार्यवाही, पटना, 1930, पीपी 1- 4)। इस प्रकार आयोग के प्रतिभागियों की सूची में भारत के प्रमुख इतिहासकारों में से लगभग 'कोईना कोई' थे।

इसके अलावा, आयोग ने रियासतों के सदस्यों को उनके कब्जे में निजी कागजात पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया। सर जदुनाथ सरकार ने 1930 में आयोग की बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में घोषित किया: "मुझे अपने सत्रों में और साथ ही साथ मेरी लगातार यात्राओं के दौरान पौराणिक कथा और बाध्यिक स्तुति के मंच से ऊपर उठकर सत्तारूढ़ राजवंशों की पिछली उपलब्धियों और उनके क्षेत्र के इतिहास की खोज करने की आवश्यकता के रूप में भारतीय राज्यों में अत्यधिक जागरूकता निर्माण करने और उन तथ्यों के प्रामाणिक आधार को सुरक्षित करने जो विदेशों में इतिहासकारों को

स्वीकार्य होंगे का आलोकन करने से खुशी हुई है। लगभग सभी महान राज्य अब अपने प्रतिनिधियों को हमारी वार्षिक बैठक में भेजते हैं। " (प्रोग्राम्स ऑफ आईएचआरसी, पटना, 1930, पीपी 7-8)। यह आशा की गई थी कि सरकारी रिकॉर्ड 'मूल राज्य' के अभिलेखों द्वारा अनुपूरक होंगे और उत्तरवर्ती "अपने रिकॉर्ड कार्यालयों को आधुनिक पद्धतियों पर व्यवस्थित करना, उनके कागजात को क्रमबद्ध करना और सूचीकरण करना और ब्रिटिश रिकॉर्ड ऑफिस में आमतौर पर देखे गए सुरक्षा उपायों के तहत सभी प्रांतों के वास्तविक शोधकर्ताओं के लिए उन्हें खुला करना शुरू करेंगे। (इबीद, पी.8)

हालांकि 1919 में रिकॉर्ड्स कमीशन का गठन, 1920 में गैर-अधिकारियों के लिए रिकॉर्ड्स खुले करने हेतु 'सार्वजनिक सत्र' का उद्घाटन, आयोग के प्रत्येक सत्र में विश्वविद्यालय के शिक्षकों को निमंत्रण और रिकॉर्ड की प्रदर्शनी आदि सकारात्मक कदम थे, फिर भी नौकरशाही को आसानी से जीता नहीं जा सका था। 1931 से सरकार ने रिकॉर्ड्स कमीशन की बैठकें बंद कर दीं। इसका स्पष्ट कारण आर्थिक तंगी था; लेकिन मेरा यह अनुमान है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के बाद से यह निर्णय राजनीतिक माहौल से असंबंधित नहीं था। जो भी कारण है, 1931 से 1937 तक आयोग की कोई बैठक नहीं हुई थी। जब 1937 में यह पूरा हुआ, तब भी हंगामा हुआ, हालांकि सरकारों के अभिलेखागार के दृष्टिकोण के कई पहलुओं के खिलाफ सौम्य भाषा में व्यक्त किया गया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रिकॉर्ड तक पहुंच पर प्रतिबंध था और एक प्रस्ताव पारित किया गया था: "भारत सरकार से अनुरोध है कि वह 1800 तक के रिकॉर्ड तक सार्वजनिक अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करे।" (आईएचआरसी की कार्यवाही, पटना, 1937, पृष्ठ 164)। यह एक समझौता था, क्योंकि कई सदस्य बाद के रिकॉर्ड तक मुफ्त पहुंच चाहते थे। इस प्रस्ताव के लिए बात करने वालों में से जहां के. ए. नीलकांत शास्त्री, बालकृष्ण, राधा कुमुद मुखर्जी, नंदलाल चटर्जी और श्री राम शर्मा जैसे अनुभवी इतिहासकार थे। रिकॉर्ड के उपयोग को उदार बनाने के लिए इस दबाव के अलावा, रिकॉर्ड खोलने के लिए लंबे समय से नौकरशाही विरोध के विपरीत, रिकॉर्ड से खोज और प्रतिलिपि बनाने के लिए लगाए गए उच्च शुल्क के खिलाफ विरोध भी थे। यहां तक कि सर जदुनाथ सरकार ने टिप्पणी की कि "श्री अब्दुल अली के कार्यालय से उन्हें प्राप्त करने से इंडिया ऑफिस [लंदन में] से टाइप की गई रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त करना बहुत आसान था।" (आईएचआरसी की कार्यवाही, पटना, 1937, पृष्ठ 161; श्री अली इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख पद पर कीपर ऑफ रिकॉर्ड थे। आयोग के सदस्यों ने सरकार से उन गैर-आधिकारिक विद्वानों पर शुल्क को कम करने का अनुरोध किया जिन्हें प्रतिबंधित पहुंच की अनुमति थी। कुल मिलाकर आयोग के गैर-सरकारी सदस्य खुले तौर पर कह रहे थे कि, समकालीन यूरोपीय कार्यप्रणाली के विपरीत, भारत सरकार जानबूझकर संकुचित नीति को अपना रही थी, जो विद्वानों के शोध और अभिलेखों तक सार्वजनिक पहुंच के प्रति प्रतिकूल थी।

ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग में विद्वानों की सलाह का कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन दो साल बाद, दिसंबर 1939 में, अभिलेखों तक पहुंच के संबंध में एक प्रमुख नीति की घोषणा की गई थी।

विधिवत प्रमाणित, वास्तविक शोधकर्ताओं, को 1880 तक सरकारी रिकॉर्ड देखने की इजाजत थी, लेकिन रिकॉर्ड से प्रतियां इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग द्वारा सेंसरशिप या जांच के अधीन थीं।

इस प्रकार स्वतंत्रता से आठ साल पहले ब्रिटिश नौकरशाही के विरुद्ध सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए एक प्रतिबंधित स्वतंत्रता धीरे-धीरे प्राप्त की गयी थी। हम इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के पिछले तीन दशकों में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख के पद में भारतीयों को शामिल करना। 1920 तक एक भी भारतीय मूल निवासी का इस पद के लिए विचार नहीं किया गया था जब बंगाल प्रांतीय सिविल सेवा में एक सिविल सेवक, राय बहादुर जामिनी मोहन मित्र को कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स की पदोन्नति में पदोन्नत किया गया था। उनके बाद उसी प्रांतीय सेवा के श्रीमान ए.एफ.एम. अब्दुल अली को ये पद मिला और 1922 से 1938 तक उनका लंबा कार्यकाल था। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख के रूप में संग्रहीत करने के काम में भारतीयों को शामिल करना एक स्वागतपर विकासशिल कदम था, लेकिन संभवतः यह निम्न ग्रेड प्रदान करने का परिणाम था जिसमें यूरोपीय अधिकारियों ने रुचि दिखाना बंद कर दिया। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, डॉ सुरेन्द्र नाथ सेन अब्दुल अली का उत्तराधिकारी बने। 1938 से 1949 तक सेन के कार्यकाल के दौरान, 'कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स' पदनाम 'निदेशक अभिलेखागार' (1944) में बदल दिया गया था और इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग का नाम बदलकर अगस्त 1947 से राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में किया गया था।

आधुनिक इतिहासलेखन और अभिलेखागार

यद्यपि इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग मूल रूप से भारतीय साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित पूर्व निर्णयों और सूचनाओं के स्रोत के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन नौकरशाही और ब्रिटिश भारतीय सरकार के उच्च निर्णय लेने के स्तर में इस राय के विपरीत विचार प्रवाह था। एक अर्थ में अभिलेखागार अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत के बारे में ज्ञान एकत्र करने और संरक्षित करने के लिए यूरोपीय ज्ञान उद्यम का हिस्सा थे। सरकार के अन्य एजेंसियों जैसे भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, या 1881 से जनगणना संचालन के साथ-साथ सरकार के अभिलेखागार ने भी इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाई। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि एडवर्ड सेड ने तर्क दिया है, इंपीरियल अधिपत्य के बारे में यूरोपीय ज्ञान को पूर्वाग्रही प्राचिन ढांचे में ढाला गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बर्नार्ड कोह और अन्य जानकारी एकत्रित करने और संरक्षित करने और उपयोग करने की सरकार की योजना के मूल में सत्ता हासिल करने के लिए बढ़ती मुहिम को इंगित करने में सही हैं। फिर भी, ज्ञान उत्पन्न करने के उस विशाल प्रयास में वहां एक जिज्ञासु भावना थी जिसने ऐतिहासिक मन को छुआ।

भारत के शुरुआती औपनिवेशिक इतिहासकारों को अभिलेखीय दस्तावेजीकरण के बिना कार्य करना था। उनमें से सबसे प्रसिद्ध जेम्स मिल (1773-1836) थे। 1820, 1826 और 1840 के प्रारंभिक

संस्करणों में ब्रिटिश भारत के उनके इतिहास में एच.एच. विल्सन 1844 संस्करण, के संपादक द्वारा कई त्रुटियों को इंगित किया गया था; उनमें से कुछ त्रुटियाँ स्रोतों के साथ और निश्चित रूप से भारत के साथ मिल की अपरिचितता के वजह से थीं। उनकी उच्च प्रतिष्ठा और प्रभाव प्रामाणिकता के कारण नहीं था लेकिन हैलीबरी में आईसीएस प्रशिक्षुओं के लिए एक पाठ के रूप में उनकी पुस्तक के चयन कारण था। मौनस्टुअर्ट एल्फिंस्टन (1779-1859) ने प्रशासन और कूटनीति में अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ-साथ ब्रिटिश इतिहास में उनके इतिहास में कुछ दस्तावेजी स्रोतों का भी ध्यान आकर्षित किया; यह नव स्थापित भारतीय विश्वविद्यालयों में एक आवश्यक पठन बन गया। सर अल्फ्रेड लाइल (1835-1912) भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का उदय और विस्तार इसके 1893 से 1911 तक कई संस्करणों में स्रोतों से विस्तार और वृद्धि हुई है; चुनिंदा स्रोतों के प्रकाशन के कारण, उनके समय में स्रोतों तक पहुंच ने, दस्तावेजीकरण का कार्य आसान बना दिया। उनके समय में अप्रकाशित स्रोतों का उपयोग दुर्लभ था क्योंकि ऐसा करने के लिए भारत सरकार ने कैप्टन जोसेफ कनिंघम को प्रताड़ित कर दिया था। बड़े पैमाने पर भारत के इन सबसे प्रतिष्ठित औपनिवेशिक इतिहासकारों के अलावा, अधिक संकीर्ण केंद्रित इतिहास या जीवनी कार्य थे, जो अधिक दृढ़ता से स्रोतों पर स्थापित किए गए थे; सर विलियम हंटर द्वारा लिखित और संपादित एंग्लो-इंडियन साम्राज्य निर्माताओं की जीवनी, ब्रिटिश लेखकों की साम्राज्य में उच्च पद के व्यक्तियों के निजी कागजात तक पहुंच के कारण विशेष रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित थी - सार्वजनिक अभिलेखों के अनुपूरक हेतु निजी कागजात के लिए इस विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच को भारतीय मूल के लेखकों के लिए इनकार कर दिया था। इस और कई अन्य फायदों के बावजूद, एंग्लो-भारतीय इतिहासकारों की औपनिवेशिक विचारधारा ने उन्हें अपने स्रोतों की पूर्वाग्रह और सीमाओं में विवेकशून्य कर दिया। उसी समय यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि उनमें से एस.सी. हिल या सी.आर. विल्सन या जी. डब्ल्यू. फोरेस्ट जैसे इतिहासकारों ने ऐतिहासिक शोध में दस्तावेजीकरण की पद्धति पर निपुणता प्राप्त की थी।

उसी समय उन्नीसवीं शताब्दी के आखिरी दशक में, इतिहास लेखन में स्वदेशी रुचि विकसित हुई, इसलिए अभिलेखीय दस्तावेजों से परामर्श करने का आग्रह किया। इस प्रक्रिया में पश्चिमी भारत में "अभिलेखागार आंदोलन" का विकास, पूर्वी भारत में इतिहास की पुनः प्राप्ति के लिए एक नया अभियान, और आम तौर पर 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शिक्षित भारतीयों के बीच ऐतिहासिक चेतना का उदय और इसलिए शोध के लिए अभिलेखागार खोलने में रुचि शामिल थी। अभिलेखों तक पहुंच से वंचित, एम. जी. रानडे (1842-1901) और के. टी. तेलंग ने अन्य के साथ-साथ पेशवा दफ्तर अभिलेखों तक पहुंच हासिल करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, इसे अभिग्रहित किया और बॉम्बे सरकार द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए रखा। 1897 में रानडे की डेक्कन वर्नाक्युलर सोसायटी ने उद्धरण बनाने और प्रकाशित करने की अनुमति मांगी, काफी विलंब के बाद अनुमति दे दी गई, बशर्ते कि रानडे की प्रस्तावना को हटा दिया गया। इसके बाद, आधिकारिक निगरानी और सेंसरशिप के तहत पेशावा रिकॉर्ड

देखने के लिए मूल निवासीयों को सरकार की अनुमति दी गई थी। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े (1863-1926) ने गैर सरकारी दस्तावेजों को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए एक आंदोलन का निर्माण किया; पुणा के भारतीय इतिहास संशोधक मंडल ने महाराष्ट्र में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल में अक्षय कुमार मैत्रेय (1861- 1930) द्वारा बंगाल के नवाब (1898 में अपनी पुस्तक सिराजुद्दलाह में प्रकाशित) का ब्रिटिशों द्वारा की गई मानहानि का जवाब देने के लिए किए गए शोध में और ब्लैक होल त्रासदी (1890 में प्रकाशित शोध) मिथक के अपने खंडन आदि में दस्तावेजी अनुसंधान के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया और इसी प्रकार एम.जी. रानडे ने अपने इतिहास पुस्तक के राइज ऑफ द मराठा पावर (1900 में प्रकाशित) में किया। 20 वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में इतिहासकारों की बाद की पीढ़ी ने भारत और इंग्लैंड में अभिलेखीय संग्रह में अनुसंधान विकसित करना जारी रखा, उदाहरण के लिए ब्रिटिश भारतीय इतिहास में सर शाफात अहमद खान, बाल कृष्ण, वी. नारायण पिल्लई, आर. वी. ओटुरकर, काली किनकर दत्ता, तारचंद, आदि सभी, और जदुनाथ सरकार, जी. एस. सरदेसाई और अन्य ब्रिटिश पूर्व इतिहास में, सभी अभिलेखीय शोध की ठोस कार्यपद्धति के आधाशिला को रखने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार 1930 के दशक में भारतीय इतिहासकारों की एक बड़ी संख्या उत्सुकतापूर्वक इंतजार कर रही थी और इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग अभिलेखागार तक पहुंच की मांग कर रही थी, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स आयोग में जदुनाथ सरकार और अन्य भारतीय इतिहासकारों ने उस मांग को आवाज दी, और इस प्रकार सरकार को 1939 में शोधकर्ताओं को इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग खोलने के लिए राजी किया गया। अब स्वतंत्रता एक दशक से भी कम दूर पर थी और औपनिवेशिक इतिहासलेखन के साथ स्पर्धा में भारतीय इतिहासकारों के अभिलेखीय शोध में एक राष्ट्रवादी व्याख्या विकसित हो रही थी।

अंत में इस रिपोर्ट में यह इंगित करना उचित होगा कि स्वतंत्रता में संक्रमण की प्रक्रिया और भारतीय गणराज्य के उद्भव में एक पहलू पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में संविधान सभा के दस्तावेजों के संग्रह में मेरे शोध के दौरान, मैंने यह पाया कि संविधान सभा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को इस संबंध में जिम्मेदारी सौंपने के लिए अभिलेखों को संग्रहित करने और संरक्षित करने के मुद्दे को संबोधित किया। संविधान के निर्माताओं ने मद 60 के तहत 'प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और रिकॉर्ड्स' शब्द डाले और इसे समवर्ती सूची में रखा। (संविधान सभा बहस, खंड IX, 31 अगस्त, 1949)। यह उस कानून पर एक सुधार था जिसे ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। 1904 में स्मारक संरक्षण अधिनियम (1904 का अधिनियम VII) द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के संबंध में भारत सरकार को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उस अधिनियम में ऐतिहासिक अभिलेखों का उल्लेख नहीं किया गया था। उस अधिनियम के बाद, संविधान सभा ने शुरुआत में संघीय वैधानिक सूची से ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बाहर रखा जहां मद 60 ने केवल प्राचीन स्मारकों का उल्लेख किया था। (संविधान सभा बहस, खंड V, 5 जुलाई 1947, 21 अगस्त, 1947)।

ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में स्मारकों के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड शामिल करना वांछनीय था और इसलिए डॉ बी. आर. अम्बेडकर ने समवर्ती सूची में रिकॉर्ड और स्मारकों को शामिल करने के लिए एक संशोधन किया। (डॉ बी. आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया संशोधन, संवैधानिक सभा बहस, खंड IX, 31 अगस्त 1949)। संविधान सभा ने अधिकारों की सूची में 'रिकॉर्ड' को शामिल करते हुए प्रस्ताव को मद सं. 67 सातवीं अनुसूची, पहली सूची, के रूप में अपनाया। (संवैधानिक सभा बहस, खंड XI, 16 नवंबर 1949)। इसके अलावा, संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों ने निर्दिष्ट किया है कि 'स्मारकों या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक हितों की वस्तुओं' की रक्षा राज्य का दायित्व होगा। संविधान सभा में सवाल उठाया गया कि क्या इस प्रावधान ने रिकॉर्ड को संरक्षित करने के उद्देश्य को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है। और यह स्पष्ट किया गया था कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस लेख में 'वस्तुओं' शब्द के तहत आए थे। (संवैधानिक सभा बहस, खंड IX, 31 अगस्त 1949, एच. वी. कामथ द्वारा दिया गया भाषण)। ऐतिहासिक अभिलेखों और स्मारकों को संरक्षित करने के मुद्दे पर भारत की संविधान सभा द्वारा दिया गया ध्यान आश्चर्यजनक नहीं हैं क्योंकि यह दृष्टिकोण इतिहास की राष्ट्रवादी दृष्टि को भारतीय सभ्यता और भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में एक रचनात्मक तत्व के रूप में दर्शाता है।

सबासाची भट्टाचार्य

अनुलग्नक संख्या ॥

कार्यपद्धति

1. मेरे द्वारा अपनायी गई डेटा संग्रह की प्रक्रिया आमतौर पर अभिलेखीय शोध में होती है: फाइलों का ढेर जो मुझे प्राप्त हुआ था इसमें से मेरे शोध प्रोजेक्ट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक फाइलों की पहचान करने के लिए इंडेक्स वॉल्यूम स्कैन (मुख्य रूप से गृह विभाग, लोक शाखा ; कुछ वर्षों में शिक्षा विभाग जब आईआरडी वहां स्थानांतरित किया गया था), करने के लिए और मेरे द्वारा चुने गए रिकॉर्ड की डिजिटलीकृत या जीरोक्स की गई प्रतिलिपियों की मांग करने के लिए। मैंने प्रतिलिपि सेवा के रूप में सामान्य शुल्क चुकाया है।
2. एनएआई में मैंने जिस प्रक्रिया का पालन किया है, वह है कि मेरे द्वारा चुने गए रिकॉर्ड से बने डिजिटल या फोटो प्रतियां का होना, और जिस पर सचिवालय सहायता के साथ कहीं और काम करना। एनएआई शोध कक्ष ने मुझे अपने दस्तावेजी स्रोतों के संग्रह के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की हैं। हालांकि, अभिलेखागार के इतिहास का विश्लेषण और लेखन के प्रयोजनों के लिए एनएआई शोध कक्ष आदर्श नहीं है क्योंकि उस कमरे में एक दर्जन या उससे अधिक लोग बैठते हैं और वहां सचिवीय सहायता संभव नहीं है।
3. 19वीं सदी के अंत और 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रकाशित इस परियोजना के प्रयोजनों के लिए मुझे जो पुस्तकें चाहिए, वह राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में उपलब्ध हैं। मैंने पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार, कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के पुराने स्थान से नए दिल्ली में अपने नए स्थान पर रिकॉर्ड के स्थानांतरण पर काफी मात्रा में डेटा प्राप्त किया। मुझे एनएआई, नई दिल्ली की तुलना में कलकत्ता के राज्य अभिलेखागार में रिकॉर्ड के हस्तांतरण पर अधिक डेटा मिला।

सबासाची भट्टाचार्य